» वर्ष: 01, अंक:13
» 1 से 15 जनवरी 2021, नि:शुल्क

न्यू इंडिया समाचार

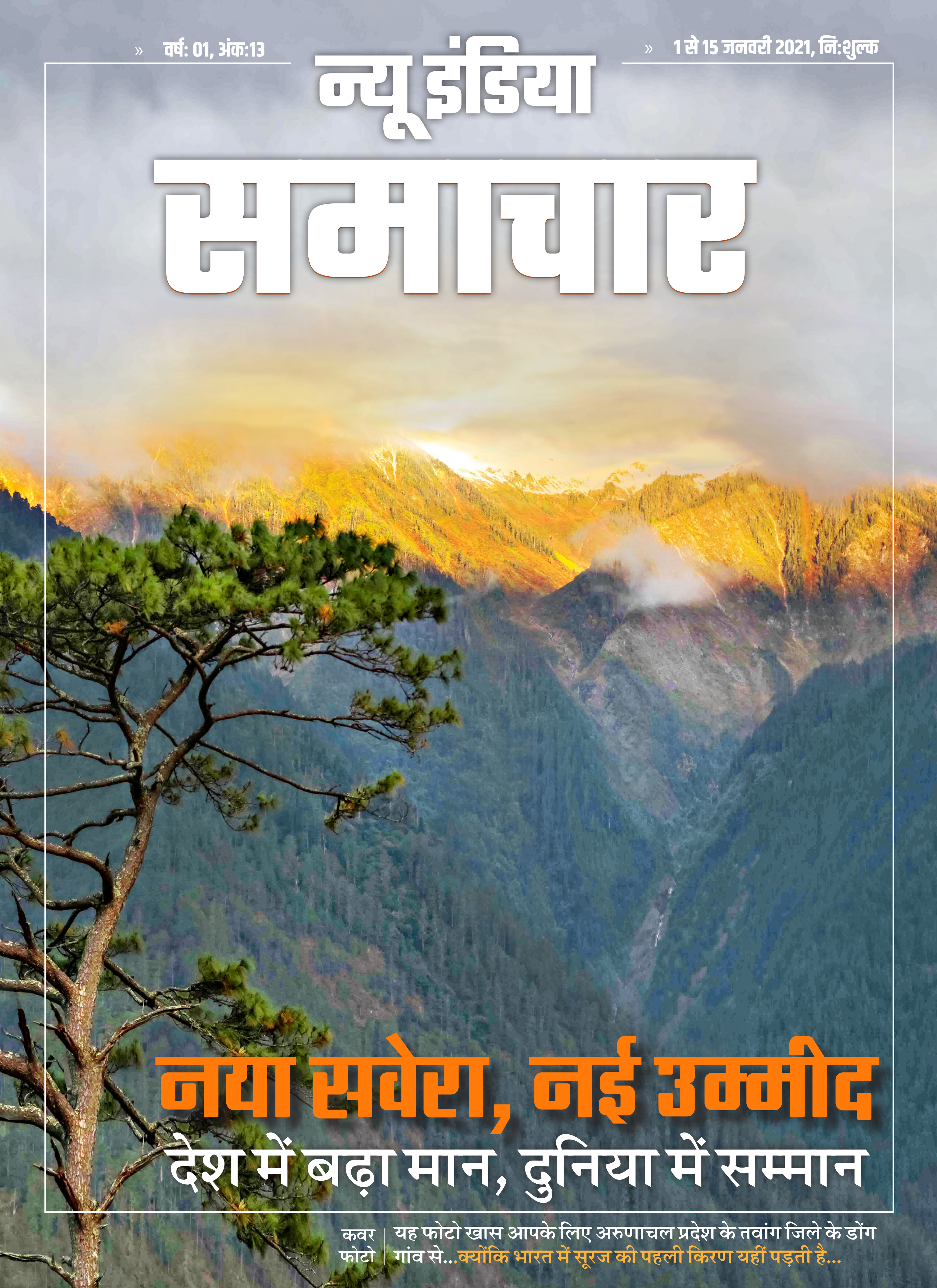

नया सवेरा, नई उम्मीद

देश में बढ़ा मान, दुनिया में सम्मान

कवर फोटो | यह फोटो खास आपके लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के डोंग गांव से...क्योंकि भारत में सूरज की पहली किरण यहीं पड़ती है...

मिलिए आत्मनिर्भर भारत चैंपियंस से

धनी राम सग्गू

जिन्होनें लकड़ी की अनोखी साइकिल बनाई

पंजाब के जीरकपुर के रहने वाले धनी राम ने लॉकडाउन के दौरान लकड़ी की साइकिल बनाई है

उनके इस इको-फ्रेंडली इनोवेशन की लोकप्रियता के कारण उन्हें कनाडा से भी ऑर्डर मिल रहे हैं

महज 4 महीनों में उन्होंने इस साइकिल को तैयार कर लिया, जो 15,000 रुपये में बिक रही है

रोशन रे

बेंगलुरु के एक फर्म ने एक इनोवेटिव इको-फ्रेंडली शुरुआत की है

रोशन रे द्वारा स्थापित सीड पेपर इंडिया ने पुराने कपड़ों को बायोडिग्रेडेबल पेपर में परिवर्तित कर दिया है जिसमें कलात्मक रुप से बीज अंतर्निहित होते हैं

इन कागजों का उपयोग विजिटिंग कार्ड या शादी के कार्ड बनाने के लिए किया जाता है जिसको बाद में किसी गमले में लगा देने से पौधे, सब्जियां या फूल उग आते हैं

एलोवेरा गांव

रांची के देवरी गांव की प्रेरणादायक कहानी

कई औषधीय पौधों लगाने के कारण देवरी गांव को 'एलोवेरा गांव' के रुप जाना जाता है

वे ग्रामीण जो पहले धान की खेती से प्रति माह 3000 रुपये कमाते थे वे अब इस नये तरीके से होने वाली कमाई से खुश हैं

इस साल धान की खेती के अलावा वे एलोवेरा के पत्तों को बेचकर अपनी आय बढ़ाने में सक्षम थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान उनकी कमाई दोगुनी हो गयी

अम्मा बागी

अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी एक उद्यमी

ईटानगर की अम्मा बागी दूरदराज के गांवों में महिलाओं को हस्तशिल्प और खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दे रही हैं

लॉकडाउन के दौरान उन्होंने स्थानीय खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए गुड़िया और खिलौने बनाने पर ध्यान केंद्रित किया

वह न सिर्फ स्वयं कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की मिसाल हैं बल्कि उन्होनें अन्य महिलाओं को भी सशक्त बनाया है

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 01, अंक: 13 | 1 से 15 जनवरी 2021

संपादक
कुलदीप सिंह धतवालिया,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

सलाहकार संपादक
संतोष कुमार
विनोद कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश,
महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20

संपर्क: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,सूचना भवन, द्वितीय तल,नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी

आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...
नया भारत, नया संकल्प

आलेख | बीते साल की यादों के साथ नए दशक के पहले साल में नए भारत का संकल्प। पेज 4-5

महिला हित...
महिला सुरक्षा से अब स्वावलंबन की ओर
पेज 10

किसानों से सरोकार...
अन्नदाता अब उपज के खुद मालिक

बीते 6 साल में किसानों के हित में सरकार के महत्वपूर्ण फैसले, साथ में नई उम्मीदें। पेज 14

उम्मीदों का अर्थ सपनों की व्यवस्था

अहम सुधार जिनकी बदौलत पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था। पेज 24-26

स्वच्छता अब जन आंदोलन
स्वच्छता का आग्रह बना संकल्प। पेज 6

धुएं से मुक्ति की ओर रसोई ...
उज्ज्वला योजना से सुविधा के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा। पेज 11

अब पटरियों पर सुरक्षा और सुविधा के साथ रफ्तार
बीते 6 साल में बदली रेलवे की तस्वीर। पेज 12

हर घर जल का सपना हो रहा साकार
जल जीवन मिशन में तय लक्ष्य से बढ़कर मिली सफलता। पेज 13

ऊर्जा का पॉवर हाउस बनता भारत
एक देश-एक ग्रिड की दिशा में अहम कदम। पेज 15

भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
पीएम स्वामित्व योजना से ऑनलाइन मिला हक। पेज 16

शिक्षा का ग्लोबल हब बनेगा भारत
नई शिक्षा नीति के साथ अब बदलाव की बयार। पेज 17

आपकी जीवनशैली अब आयुर्वेदिक
विरासत को देश के साथ दुनिया में मिला सम्मान। पेज 18-20

अब जय विज्ञान, जय अनुसंधान
इंटरनेट और इनोवेशन के रास्ते सशक्त हो रहा देश। पेज 21

लोकतंत्र का नया मंदिर
नए संसद भवन में मनेगा आजादी का 75वां पर्व | पेज 22-23

काशी विश्वनाथ भव्य रूप में 2021 में लेगा आकार। पेज 27
आपका पासपोर्ट आपकी ताकत। पेज 28-30
आधारभूत ढांचा विकास की नई इबारत। पेज 31
कानूनी जाल से मिली मुक्ति। पेज 32
एक देश-एक व्यवस्था। पेज 33
एक देश, एक विधान, एक निशान का सपना साकार। पेज 34-35
पूर्वोत्तर की पहचान बनेगा कश्मीर का केसर। पेज 36
सरहदें सुरक्षित हैं इनके दम से। पेज 37-39
कैबिनेट के फैसले। पेज 40

युवा भारत-सशक्त भारत
स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती पर विशेष...न्यू इंडिया के सपने को गढ़ने में युवाओं की भूमिका और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता । पेज 7-9

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार।

आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यह साल देश-दुनिया सबके लिए खास है क्योंकि हम नए दशक के पहले साल में प्रवेश कर रहे हैं तो बीते दशक के आखिरी साल की कुछ कड़वी यादें हैं जिन्हें हर कोई भूलना चाहेगा। लेकिन आपदा हमेशा अपने साथ कुछ सीख लेकर आती है, ऐसे में नजरिया हमेशा आशावादी होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण हमेशा से आशावादी रहा है और वे कई मौकों पर कहते भी रहे हैं कि गिलास में आधा पानी हो तो उसे आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ गिलास मानें। यही वजह है कि इस आपदा को उन्होंने ऐसे अवसर में तब्दील किया कि आज भारत में आत्मनिर्भरता एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और लोग लोकल के लिए वोकल होने लगे हैं। कठोर से कठोर निर्णय लेना और उसे जमीन पर साकार करने की सोच का ही नतीजा है कि बीते दशक के आखिरी छह साल में सरकार ने जिस तरह समग्र सोच के साथ योजनाएं और नीतियां बनाई उससे भारत एक नई सुबह देख रहा है। यही नहीं, नए साल में जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर कोरोना वैक्सीन पहले चरण में किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी समेत टीकाकरण की पूरी तैयारी केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है।

वैसे तो इन वर्षों में 450 से ज्यादा योजनाएं सरकार जमीन पर साकार कर चुकी है। लेकिन हम इस बार आपकी अपनी पत्रिका- 'न्यू इंडिया समाचार' में 21 चुनिंदा क्षेत्रों के साथ बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत में नई भोर हो रही है और उम्मीदें उफान मार रही हैं।

भारत की सफलता सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 21 वीं सदी के नए दशक में वह दुनिया के लिए भी उम्मीद की किरण बनकर उभरा है।

इन उम्मीदों को साकार करने में 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प पूर्व की तरह ही अपेक्षित है ताकि नया सवेरा देख रहा भारत अब नई उम्मीदों के साथ निरंतरता बनाए रखे।

एक बार फिर नववर्ष- 2021 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

अपने विचार और सुझाव हमसे साझा करते रहिए...

पता- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003

ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

कुलदीप

(कुलदीप सिंह धतवालिया)

आपकी बात...

देश और समाज हित में 'न्यू इंडिया समाचार' एक सशक्त और सार्थक पहल है। समसामयिक विषयों पर प्रकाशित आलेख देश और समाज के विकास का दर्पण बन कर पत्रिका को नवीनतम जानकारियों के प्रसार का एक मजबूत और प्रमाणिक माध्यम बनायें, ऐसा प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए।

त्रिलोक चन्द्र भट्ट
tcbhatt14@gmail.com

मुझे दिनांक 1 से 15 दिसंबर का अंक मिला इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका के इस अंक में बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के बारे में जो लेख उनके जन्मस्थली और महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में लिखा गया है। मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई और इस पत्रिका के माध्यम से देश की जनता को एक अच्छा संदेश पहुंचाने का काम किया है। धन्यवाद!

अशोक कुमार
theharidwarreporter12@gmail.com

16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 का न्यू समाचार पत्र पढ़ने का अवसर मिला। बहुत ही सुंदर प्रयास और सभी लेख सराहनीय लगे ।संपादक महोदय एवं प्रधान संपादक महोदय को हार्दिक धन्यवाद।

श्रीगोपाल
shrigopal6@gmail.com;

'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका का 1 से 15 दिसंबर 2020 का अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका में प्रकाशित सभी स्तंभ ज्ञानवर्धक सामग्री से भरपूर रहे। आकर्षक साज-सज्जा के साथ सरकारी योजनाओं से संबंधित पठनीय सामग्री प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

प्रमोद कुमार अग्रवाल

मैं ओंकार अवदान, अब मैं सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं और मैं एक ऐसे मैजीन की खोज कर रहा था, जो मुझे भारत के बारे में एक विशिष्ट, विशिष्ट और संपूर्ण 'समचार' दे सके। मुझे SSC पोर्टल पर NIS मैग्जीन का लिंक मिला और मेरी खोज यात्रा समाप्त हो गई। यहां मैं भारत के बारे में हाल की सभी खबरों को निःशुल्क पढ़ सकता हूं। धन्यवाद ... न्यू इंडिया समचार

ओंकार अवदान
awadanomk98@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार का प्रत्येक अंक मुझे पढ़ने को प्राप्त हो रहा है इसके लिए बहुत साधुवाद। साथ ही साथ समाचार लिखने वाले लेखकों को भी बहुत ही साधुवाद। शब्द चयन की अनुपम श्रृंखला नए समाचारों से भरपूर सामान्य ज्ञान से भरपूर, साथ ही साथ इसमें कुछ सहभागिता की जरूरत है। जैसे हमारे बहुत से बड़े बड़े अफसर देश के प्रति बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे है उनके इंटरव्यू प्रकाशित किए जा सकते हैं ।

अरुण कुमार तिवारी
aruntiwari.rewa143@gmail.com

नया भारत, नया संकल्प

कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के साथ वर्ष 2020 में मानवता ने जिस तरह के कष्टों का झेला है, उस नाते निश्चित ही आप इसे जल्द भूल जाना चाहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जिन्हें इस वर्ष के साथ आपको याद रखना चाहिए। वर्ष 2020 ही वह साल है जिसने हमें तमाम परेशानियों के साथ आपदा में भी अवसर तलाशने को प्रेरित किया है। यही वो साल है जब लोकल के लिए वोकल के पथ पर चलते हुए हम 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इसलिए तमाम परेशानियों और बुरे वक्त के लिए भले ही इस वर्ष को भूल जाइए...पर यह तीनों संकल्प जरूर याद रखिए। क्योंकि आने वाले नए साल में इसी रास्ते पर चलकर हमारा देश प्रगति की एक नई कहानी लिखेगा... और हां...साथ में नमन कीजिए उन योद्धाओं को जिन्होंने इस मुश्किल समय में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया ताकि हम सुरक्षित रहें...

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा...

भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की करीब चार दशक पहले किया उद्घोष 21वीं सदी के नए भारत का संकल्प बन गया है। आज भारत न सिर्फ नया सवेरा देख रहा है, बल्कि नई सदी के नए दशक में नई उम्मीदें भी उफान भरने को तैयार है। इसकी वजह है कि 2014 में देश की सत्ता ही नहीं, देश का मूड भी बदला। 130 करोड़ देशवासियों का बदला मिजाज ही नए भारत की नींव तैयार करने में सहायक साबित हुआ है। छह साल पहले भारत की तस्वीर ऐसी थी मानो सिस्टम ठप है, नकारात्मकता का घेरा बढ़ रहा था। भ्रष्टाचार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, किसानों के लिए जरूरी खाद की कालाबाजारी जैसी कई समस्याओं का अंत

130 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही है न्यू इंडिया और इस सपने को पूरा करने की हमारे भीतर इच्छा भी है और दृढ़ संकल्प भी

होता नहीं दिख रहा था। ऐसे में 2014 का आम चुनाव निराशावाद बनाम आशावाद का प्रतीक बना और भारत की जनता को भी नई भोर का अहसास हुआ। 'लोकतंत्र' से 'लोक' जुड़ा और नौकरशाही को सही मायने में लोकसेवक बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को 'प्रधान सेवक' बनाया। न खाऊंगा और न खाने दूंगा को शासन का ऐसा मंत्र बनाया जिस पर चलने के लिए खुद 16 से 18 घंटे काम करते हुए मिसाल पेश की। प्रशासनिक सुधार, बिजली सुधार, रेल सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश, टैक्स पारदर्शिता, जीएसटी से एक देश-एक टैक्स, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद की सहज उपलब्धता, शिक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव, दुनिया में भारत की ताकत को मजबूती दिलाने जैसे क्रांतिकारी बदलाव का साक्षी बना है बीता दशक।

सिर्फ आधारभूत बदलाव ही नहीं, गरीबों को उसका हक दिलाना, उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई का सपना साकार करना, हर घर तक लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए नल से जल उपलब्ध कराने की भागीरथी योजना की पहल, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त 5 लाख रु. तक की ईलाज की सुविधा दिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर योजना को लागू कराना, सबको बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए जन-धन जैसी योजना को मूर्त रूप देना और छह दशक के फासले को बीते छह साल में कम करते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा भारत को नए उजाले की तरफ लेकर जाना मौजूदा सरकार की कार्यशैली के कुछ उदाहरण है जो 'न्यू इंडिया' के निर्माण में नींव बनी है। पड़ोसी देशों की नापाक इरादों को उसके घर में घुसकर ध्वस्त करने वाले भारत के इरादे आज बुलंद हैं।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा भारत को नए उजाले की तरफ लेकर जाना मौजूदा सरकार की कार्यशैली के कुछ उदाहरण है।

अभी जब हम नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, तब ये ध्यान रखना होगा कि दुनिया अब पहले जैसी कभी नहीं होने वाली है। जीवनशैली से लेकर अर्थव्यवस्था में और जीवन में व्यवहारगत परिवर्तन अपरिहार्य लग रहे हैं। भारत इन परिवर्तनों में अपवाद नहीं होगा। इस परिवर्तन को कम से कम हंगामे के साथ साकार करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की साफ प्राथमिकता होगी। उनके भीतर बैठे स्थिर और मजबूत नेता ने इस महामारी से पैदा हुए संकट का प्रबंधन करने में और आजादी के बाद देश के सबसे कठिन वक्त में देश का नेतृत्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस दौरान कुछ लोगों की आजीविका चली गई होगी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया होगा, वहीं कई अन्य लोग अब काम पर लौट आए होंगे क्योंकि 13 मई के बाद तीन किश्तों में 29.87 लाख करोड़ रुपये की लागत के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की ताकत पर अर्थव्यवस्था ने वापसी की है।

कोविड के दौर में सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। गांव, गरीब, मध्यम वर्ग से लेकर उद्योगों तक की चिंता का नतीजा है अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी

कोविड के कठिन दौर में खाद्यान्न से लेकर नकद सहायता और कर्ज से लेकर सब्सिडी तक, सरकार ने जो जो कहा था वो सब करके दिखाया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना की सहायता से 45 लाख से अधिक छोटे व्यवसायों ने बड़ी संख्या में औपचारिक और अनौपचारिक नौकरियों को बचाते हुए अपने कामकाज जो बहाल कर लिया है। 80.93 लाख उधारकर्ताओं को 205,563 करोड़ रुपये से भी ज्यादा मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 158,626 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। और भी किए जाने हैं। ये केवल एक डेटा है जो इशारा करता है कि पूर्ण आर्थिक रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं, उस नए साल के लिए जो असल अतियथार्थवाद प्रकट करेगा। ये अतियथार्थवाद भारत के आर्थिक विकास की संभावनाओं पर स्वतंत्र कंसल्टेंसी कंपनियों की टिप्पणियों में झलकता है।

ऐसे में जब हम भारत के लोग बीते छह साल में भारत में नया सवेरा देख रहे हैं तो 21वीं सदी के दूसरे दशक के पहले साल में नई उम्मीदों को पूरा करने में भी देश की जनता के अटल इरादे आवश्यक हैं। अगर बीते छह साल में भारत ने एक पड़ाव हासिल किया है, लेकिन यह मंजिल नहीं है। नए भारत का लक्ष्य सामने है, ऐसे में अटल जी ही कविता की पंक्तियों के साथ हम नए दशक के पहले साल में इस संकल्प के साथ आगे बढ़ें- "आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।"●

स्वच्छता अब जन आंदोलन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, 'हर कोई खुद का सफाई कर्मी है। स्वतंत्रता से स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते, तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को साफ नहीं कर सकते।' बापू के 150वें जयंती वर्ष पर स्वच्छ भारत का उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत अब अभियान से बढ़कर जनआंदोलन बन चुका है।

उम्मीदें हुईं पूरी...

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

10.73 करोड़

शौचालय बनाए गए

देशभर के 706 जिलों के 6.03 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त। अक्टूबर 2019 में सभी जिलों ने खुद को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया।

ओडीएफ घोषित 4340 शहर में 1,319 को ओडीएफ+, 489 शहरों को ओडीएफ++ प्रमाणन मिला।

स्वच्छ शहर सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में 4242 शहर, 62 छावनी बोर्ड और 97 गंगा शहरों का सर्वेक्षण जिसमें 12 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया।

सामाजिक कल्याण योजना से जुड़े 5.5 लाख स्वच्छता कर्मी और 84,000 कचरा बीनने वालों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। निकायों ने 4 लाख से ज्यादा अनुबंधित कर्मचारियों को काम पर रखा।

देश के 77% वार्ड में कचरा पृथक्करण संसाधन उपलब्ध, 67% में शोधन किया जा रहा है। ये 2014 के 18 फीसदी की तुलना में करीब चार गुना है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 62,28,372 शौचालय बनाए गए। सरकार ने 58,99,637 घरेलू शौचालय का लक्ष्य रखा और लक्ष्य के मुकाबले 106 फीसदी 62,28,372 शौचालय बनाए गए। 4372 शहरों के 83,434 वार्डों में घर से कचरा कलेक्शन भी होने लगा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में स्वच्छता अभियान के चलते 3 लाख जान बचीं।

75, 50,000 फुल टाइम जॉब

यूनिसेफ के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में अक्टूबर 2014 से फरवरी 2019 के बीच लोगों को काम मिला।

₹ 53,000 प्रति परिवार बचत

यूनिसेफ के अनुसार खुले में शौच मुक्त गांव में बीमारी, मृत्यु में कमी और समय की बचत से प्रति परिवार सालाना 53 हजार रु. की बचत हुई।

अब नए सपने की ओर...

₹1,40,881

करोड़ का अनुमानित बजट आवंटित किया गया है ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-दो में वर्ष 2024-25 तक।

ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने सितंबर, 2019 में एक 10 वर्षीय स्वच्छता कार्यनीति (एक्शन प्लान) तैयार किया है।

ओडीएफ+, ओडीएफ++, कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण से सतत स्वच्छता का मार्ग तेजी से अग्रसर होगा।

फिर होगी स्वच्छता की जीत, सर्वेक्षण 2021- बनाए अपने शहर को नंबर-एक, 4 जनवरी से 21 जनवरी, 2021 तक होगा सर्वेक्षण।

गूगल मैप पर आए 2900 शहरों के 59,900 से अधिक शौचालय की संख्या में होगी तेजी से वृद्धि।

ताजा सर्वेक्षण में इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई, सूरत,राजकोट और मैसूर को पांच स्टार तथा 86 शहरों को तीन स्टार रेटिंग मिली। 5 स्टार रेटिंग के लिए इस बार कड़ी प्रतियोगिता होगी।●

युवा भारत-सशक्त भारत

सबसे युवा देश हमारा औसत आयु 29 साल

आज हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। भारतीयों की औसत आयु 29 साल है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ युवा ताकत के दम पर भारत की विकास दर 02 फीसदी तक और बढ़ सकती है।

भारत की कितनी आबादी किस उम्र की...

50 फीसदी से ज्यादा आबादी की आयु 25 साल से कम

65 फीसदी से ज्यादा आबादी की आयु इस समय 35 साल से कम है।

62 फीसदी आबादी (15-59 साल) श्रम बल के दायरे में

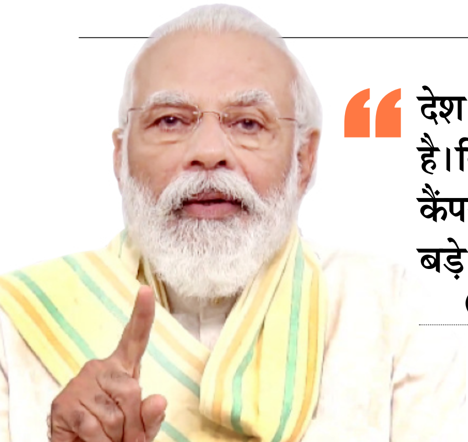

"देश के युवाओं के बीच होना तरोताजा करने वाला और ऊर्जा से भरने वाला होता है। विश्वविद्यालय के परिसर मिनी इंडिया की तरह होते हैं। एक तरफ जहां इन कैंपस में भारत की विविधता के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यू इंडिया के लिए बड़े बदलाव का जुनून भी दिखाई देता है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री"

(देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों से संवाद पर मन की बात में जिक्र करते हुए)

मिशिगन विश्वविद्यालय में चर्चा के दौरान स्वामी विवेकानंद से एक सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा-यह सदी आपकी है, 21वीं सदी हमारी होगी। 35 साल की उम्र तक की आबादी वाले 65 फीसदी युवाओं के साथ भारत आज 127 साल पहले अमेरिका में कहे गए स्वामी विवेकानंद के इस कथन को सिद्ध करने की दिशा में अग्रसर है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है।

'न्यू इंडिया' के सपने को गढ़ने में भारत के युवा सबसे अहम हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवा शक्ति का जिक्र करते हुए कहा था, "देश का युवा ही दुनियाभर में ब्रांड इंडिया का ब्रांड एंबेसडर है। हमारे युवा भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनसे अपेक्षा सिर्फ हजारों वर्षों से चली आ रही भारत की पुरातन पहचान पर गर्व करने भर की ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भारत की नई पहचान गढ़ने की भी है।"

युवाओं को स्किल, रिस्किल और अपस्किल करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार नई योजनाओं और कार्यक्रमों पर काम कर रही है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे तमाम कार्यक्रम देश के युवाओं के सपनों को ही साकार करने की दिशा में अहम कदम हैं।

सपनों का सूर्योदय

स्किल इंडिया मिशन

1,00,00,000

युवाओं को हर साल प्रशिक्षित किया जा रहा है। 5 साल में करीब 5 करोड़ युवा प्रशिक्षित

कौशल प्रशिक्षण केंद्र

704 जिलों में 720 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है।

5 हजार नए आईटीआई। 34 लाख युवाओं को लोन उपलब्ध कराया गया।

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

नेशनल कॅरियर सर्विस

एक मंच पर सभी नौकरियों की जानकारी मिले इसके लिए नेशनल कॅरियर सर्विस की शुरुआत की गई।

1,02,74,899

युवा, 81,158 नियोक्ता जुड़ चुके हैं 10 दिसंबर 2020 तक। 71,024 रिक्त नौकरियों की सूचना उपलब्ध

- बदलते वक्त के अनुसार केंद्र सरकार ने 33 साल बाद नई शिक्षा नीति की शुरुआत की, जिसमें पहली बार रटने से ज्यादा सीखने और अपनी स्किल बढ़ाने के साथ शोध पर जोर दिया गया है। भाषा के बंधनों को हटाते हुए नई शिक्षा नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि हर व्यक्ति को बेहतर और अच्छी शिक्षा मिले।
- सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं की सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है।
- पिछले 5 सालों में 16 नए आईआईटी, 7 नए आईआईएम की शुरुआत की गई। मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 22 नए एम्स खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- 37 हजार करोड़ रुपये खर्च कर 75 शिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया गया। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के 'स्वयं-2' की पहल की गई।
- स्किल इंडिया मिशन और नेशनल अप्रेंटिशप प्रमोशन स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए जरूरी धन मुहैया कराया जा रहा है।
- पेटेंट की संख्या 4 गुना तक हुई है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई। रोजगार सृजन की दिशा में भारत बीपीओ संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है।
- खेल कोटे के तहत नौकरियों में मलखंभ, सेपकटकरा समेत 20 नए खेलों को जगह दी गई है। खेलो इंडिया और पोडियम फिनिश जैसे कार्यक्रम की बदौलत छोटे शहरों से खिलाड़ी उभर रहे हैं तो प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। नई प्रतिभाओं की तलाश के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व में 5 जोन बनाए गए हैं।
- नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की गई है।

50,000

स्टार्टअप के साथ आज भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है।

इसने न केवल युवा सपनों को राह दिखाई है, बल्कि इसके माध्यम से स्टार्टअप की शुरुआत से लेकर स्थापित रूप में आने तक केंद्र सरकार की ओर से मदद मुहैया कराई जा रही है।

प्रधानमंत्री mudra योजना **₹10,00,000**

करोड़ से ज्यादा लोन दिया मुद्रा योजना में 26 करोड़ से ज्यादा नए उद्यमियों को

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक भारत में आत्मनिर्भर युवाओं की संख्या 3.30 करोड़ (2016) से बढ़कर 2019 में 5.60 करोड़ हो गई। रोजगारों में स्वरोजगार का हिस्सा 14% हो गया।

उम्मीदों का नया सवेरा

Skill India कौशल भारत-कुशल भारत

40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण

स्किल इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा बल्कि उन्हें प्रमाण पत्र के रोजगार में भी सहयोग का लक्ष्य रखा गया है।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। शिक्षा के विकास, मूल्यांकन और नीतियों लागू करने का काम करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बनाया जाएगा।

50

उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 50 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य है। फ़िलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार यह 26.3 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी।

- आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स और तकनीक के नए क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा।
- नैसकॉम के मुताबिक, 2025 तक स्टार्टअप 50 लाख रोजगार देंगे। इनमें से 11 लाख प्रत्यक्ष और 39 लाख अप्रत्यक्ष होंगे।
- पांच साल में नौकरी देने में यूनिकॉर्न स्टार्टअप (एक अरब डॉलर से ज्यादा कारोबार वाले) प्रमुख भूमिका निभाएंगे। पिछले साल 24 यूनिकॉर्न ने 60 हजार से ज्यादा प्रत्यक्ष और 1.8 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा किए।
- इंडिया स्किल रिपोर्ट-2020 के अनुसार, मिलेनियल्स (21वीं सदी में किशोरवय पाने वाले) देश के श्रमबल का 47 फीसदी हिस्सा हैं।

महिला: सुरक्षा से स्वावलंबन की ओर

जब महिलाएं विकसित होंगी तो देश और समाज भी सही मायने में विकसित व सशक्त हो सकेगा। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "भारत में महिला शक्ति को जब-जब भी अवसर मिले, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश को मजबूती दी है।" इसी सोच का आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक महिला सुरक्षा से लेकर, उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण, रसोई से लेकर सेना में लड़ाकू भूमिका तक महिला हित में अनेक फैसले किए हैं।

महिला हित में नया सवेरा

मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए तीन तलाक की प्रथा को कानून बनाकर खत्म किया गया। आजादी के 70 साल बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए हज यात्रा में 'महरम' (पुरुष अभिभावक) की अनिवार्यता खत्म की गई।

1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट

महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों की पहचान के लिए नेशनल डेटा बेस बनाया। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए देशभर में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं।

- 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म पर फांसी की सजा। दुष्कर्म के मामलों में 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का कानून बनाया।
- देश के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। देश में 600 से अधिक वन स्टॉप सेंटर शुरू किए गए।
- नई टैक्सी नीति के तहत हर टैक्सी में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य।
- महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति। तीनों सेनाओं में स्थाई कमीशन।
- महिला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 6 करोड़ 60 लाख से अधिक महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़ा गया।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं को 5000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में दी जा चुकी है।
- मिशन इंद्रधनुष के तहत 90 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 22 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खोले गए। कोरोना काल में 500-500 रु. 3 किस्तों में इन्हीं खातों में भेजे गए।
- प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों से1 रुपये में सैनेटरी नैपकिन की शुरुआत की गई।
- केंद्र तथा राज्य सरकारों ने 350 से ज्यादा योजनाएं एक साथ 'नारी' पोर्टल पर उपलब्ध।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 104 जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ। मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। मुद्रा योजना में लोन, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत

उम्मीदों का नया उजाला

- महिलाओं के लिए भारत को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम।
- मनरेगा से लेकर स्टार्ट अप के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही।
- मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया में 12 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिला लाभ, अब आने वाले समय में उसका दायरा बढ़ाने पर सरकार का जोर।

रसोई: धुएं से मुक्ति की ओर...

इस दुनिया में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। खासतौर से महिलाओं के लिए जो समाज के साथ अपने परिवार की धुरी होती हैं, उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने के लिए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन देने का असर है कि अब देश के 98 फीसदी घरों में रसोई गैस पर खाना बनता है। स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में उज्ज्वला योजना बनी अहम कदम...

पूरे हो रहे हैं सपने...

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सितंबर 2020 तक 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। यह लक्ष्य तय समय से 7 महीने पहले हासिल कर लिया गया है।

साफ ईंधन यानी गैस पर खाना बनाने वाले परिवारों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इस पहल से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बन गया है।

5 वर्ष पहले देश के सिर्फ 55% परिवारों में ही रसोई गैस पर खाना बनता था, वहीं आज यह आंकड़ा 98% पहुंच गया है। यानी रसोई गैस पर खाना बनाने वाले परिवारों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में रसोई में पारंपरिक ईंधन जैसे-लकड़ी, कोयला आदि पर खाना बनाने के चलते प्रतिवर्ष करीब 5 लाख मौतें होती थीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण महिलाओं में सांस संबंधी बीमारी के मामलों में 20 प्रतिशत कमी आई है।

अगस्त 2020 तक इस योजना के तहत 1306.87 लाख रीफिल सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं।

अब उम्मीदों की ओर...

उज्ज्वला योजना के तहत तय किए गए 8 करोड़ कनेक्शन से आगे बढ़ कर अब केंद्र सरकार 10 करोड़ परिवारों तक निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने पर काम कर रही है। इसके लिए उज्ज्वला योजना के प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना देश के सभी 28 करोड़ परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने की है।

स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय के साथ केंद्र सरकार अब इससे आगे बढ़कर पाइप्ड नेचुरल गैस(पीएनजी) और लिक्विड नैचुरल गैस(एलनजी) के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

इसके तहत वर्ष 2030 तक प्राकृतिक गैस का उत्पाद 15 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की योजना है। अभी यह 6.2% है। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में यह अहम कदम है। कोयला-डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन के बजाय फैक्ट्रियों में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़वा दिया जा रहा है

वर्ष 2030 तक देश में 10000 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगेगी।

98% परिवार में रसोई गैस पर बनता है खाना

कोरोना काल के बीच अप्रैल-जून में इस योजना के तहत 11.97 करोड़ एलपीजी सिलेंडर दिए गए।

8 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके और अब **10** करोड़ परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य

उज्ज्वला योजना के तहत 2016-17 में 200.3 लाख, 2017-18 में 155.7 लाख, 2018-19 में 362.9 लाख और 2019-20 में 82.64 लाख निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

अब पटरियों पर सुरक्षा और सुविधा के साथ रफ्तार

भारतीय रेल नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं में ढाली जा रही है। बीते 6 साल में पहले से अधिक स्वच्छ, मानव रहित फाटकों से मुक्त, एक साल से अधिक समय तक मानव हानि वाली दुर्घटना से मुक्त होने की उपलब्धि के साथ सुरक्षित हुई है। रफ्तार तेज हुई है, वंदे भारत जैसी स्वदेशी, सेमी-हाईस्पीड ट्रेन नेटवर्क का हिस्सा बन रही है। देश के अनछुए हिस्से तक रेलवे को जोड़ने, रेल मार्गों के चौड़ीकरण, 100 फीसदी विद्युतीकरण, जीरो कार्बन के साथ हरित रेलवे और हाईस्पीड कॉरिडोर की उम्मीदों के साथ नए साल में प्रवेश कर रही है।

नया सवेरा

- बिहार में कोसी रेल मेगा ब्रिज शुरू, ब्रिज से कोसी और मिथिलांचल आपस में नौ दशक बाद जुड़े। इस 2 किमी लंबे ब्रिज निर्माण का शिलान्यास 2003-2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था।
- भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से बाहर बांग्लादेश के बेनापोल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की।
- भारतीय रेलवे की 18,065 किमी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण नवंबर, 2020 तक किया जो 2009-2014 की तुलना में 2014-2020 के पांच साल में 371% अधिक का रिकॉर्ड है।
- रेलवे ने 27 लाख सेवारत व सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है।
- किसान रेल गाड़ियों में अधिसूचित फल और सब्जियों की ढुलाई में किसानों को 50% सब्सिडी। **सुरक्षित रेलवेः** अप्रैल, 2019 से जून, 2020 तक रेल दुर्घटना में एक भी यात्री की मृत्यु नहीं। 1853 में रेलवे की शुरुआत से अब तक पहली बार यह उपलब्धि हासिल की है।
- 2018-19 में 631 के मुकाबले 2019-2020 में 1274 मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग खत्म। वित्तवर्ष 2019-20 में 5181 किमी रेल पटरियों का नवीनीकरण, 1309 पुल बनाए और 1367 की मरम्मत।
- हरित रेलवे के लिए 505 जोड़ी ट्रेन में हेडऑन जनरेशन तकनीक लगाई। इससे 7 करोड़ लीटर डीजल या 450 करोड़ रुपए बचत की संभावना। 69 हजार डिब्बों में 2.44 लाख बायो टॉयलेट लगाए।

नई उम्मीदें

- दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड कॉरिडोर(800 किमी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) में नई लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग सर्वेक्षण तकनीक व हेलीकॉप्टर की मदद से होगा जमीन का सर्वेक्षण।
- भारतीय रेलवे ने दिसंबर, 2023 तक 28143 किमी बड़ी रेलवे लाइन नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण का रखा लक्ष्य, नवंबर, 2020 तक 66 फीसदी पूरा।
- बड़ोदरा स्थित नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ने 7 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जिसमें स्नातक स्तर के 2 बी.टेक, 2 एमबीए और 3 एमएससी पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से साझेदारी वाले पाठ्यक्रम में छात्रों को मौका मिलेगा और रेलवे को एक्सपर्ट मिलेंगे।
- रेलवे में 1.4 लाख पदों के लिए भर्ती परीक्षा की शुरुआत की जा रही है।
- भारतीय रेलवे 2030 तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली जन परिवहन नेटवर्क में बदलने पर कर रही है काम, बिना उपयोग वाली जमीन पर 2 गीगावाट की सौर परियोजना लगेगी। पटरियों पर एक गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी तैयारी।
- रेलवे के सभी डिब्बों में दिसंबर, 2022 तक आरएफआईडी टैगिंग होगी जिससे कौन सा कोच कहां है इसकी जानकारी तुरंत मिल सकेगी।
- अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन योजना और रफ्तार पकड़ेगी। पलवल से सोहना-मानेसर-खरखौदा होते हुए सोनीपत तक ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी।

हर घर जल
का सपना हो रहा साकार

आजादी के बाद 70 साल में जिस देश में सभी लोगों के पीने का पानी न मिल पाता हो, वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में लाल किले की प्राचीर से 5 साल के भीतर हर घर में पानी के कनेक्शन का सपना देखा तब कई लोगों ने इस पर संदेह जताया। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के सपने को पूरा करने के लिए रोज 88 हजार नल कनेक्शन का लक्ष्य लेकर चली केंद्र सरकार अब भागीरथी संकल्प को साकार करते हुए रोज 1 लाख घरों को जोड़ रही है ...

पूरे हो रहे हैं सपने...

गोवा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां हर घर में नल कनेक्शन है। इसी के साथ 16 जिलों, 402 ब्लॉक, 31,848 पंचायत और 57,935 गांव के 100% घरों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। साथ ही श्रीनगर और गंदरबल में भी 100% नल कनेक्शन हो चुके हैं।

'ईज ऑफ लिविंग' के मिशन के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार सबको घर, बिजली, शौचालय, स्वच्छता के साथ पीने के पानी की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है।

प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त 2019 को लाल किले से इसकी घोषणा की तब तक 81 फीसदी आबादी स्वच्छ पीने के पानी से दूर थी। दिसंबर 2020 तक कुल 6 करोड़ परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है।

कोरोना जैसी महामारी के बीच अनलॉक-1 के बाद 45 दिनों में जल जीवन मिशन के तहत देश के 45 लाख घरों में नल कनेक्शन।

50 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की

गांवों में इस मिशन को पूरा करने के लिए बनाई गई समितियों में 50% हिस्सेदारी महिलाओं की।

अब उम्मीदें होंगी पूरी

वर्ष 2022 तक इन राज्यों के हर घर में नल कनेक्शन

●उत्तर प्रदेश ● गुजरात ● हरियाणा ●हिमाचल प्रदेश ● जम्मू-कश्मीर ● लद्दाख ● मेघालय ● पंजाब,सिक्किम।

वर्ष 2023 तक इन राज्यों के हर घर में नल कनेक्शन

●अरुणाचल प्रदेश ●कर्नाटक ● मध्य प्रदेश ● मणिपुर ●मिज़ोरम ● नागालैंड ● छत्तीसगढ़ ●त्रिपुरा

वर्ष 2024 तक इन राज्यों के हर घर में नल कनेक्शन

●राजस्थान ●असम ●प.बंगाल ●आंध्र प्रदेश ● झारखंड, महाराष्ट्र ●केरल ●ओडिशा ●तमिलनाडु ● उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री गरीब रोजगार कल्याण अभियान को भी जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को काम देने की योजना है। इसके तहत 6 राज्यों में 25 हजार गांवों में काम किया जाना है। इसके अलावा भी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

देश के सभी स्कूल-आंगनबाड़ी इस साल नल कनेक्शन से जुड़ जाएंगे। 100 दिन की इस कार्ययोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को की गई थी।

अन्नदाता अब उपज के खुद मालिक

स्वामीनाथन आयोग की जिन सिफारिशों को पूर्ववर्ती सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, वर्ष 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लागू किया। 28 फरवरी 2016 को बरेली में आयोजित किसान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, " आने वाले 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी।" इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार जहां फसलों के समर्थन मूल्य में लगातार इजाफा किया है तो बुवाई से पहले, बुवाई के दौरान और बुवाई के बाद तक हर स्तर पर किसानों को मदद दी जा रही है।

खुशहाली की सौगात...

22.39 करोड़
मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभी तक बांटे गए हैं, ताकि किसानों को सही फसल चुनने में मदद मिल सके।

ऊर्वरकों की कीमतों में कमी की गई। 100 फीसदी नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध कराया। कम ब्याज पर ऋण की सुविधा।

फसल के लिए वैज्ञानिक सलाह एसएमएस और कॉल के माध्यम से सुनिश्चित की गई। सबसे कम प्रीमियम दर के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। किसान मानधन योजना में 3000 रु. की पेंशन की शुरुआत की गई।

कोविड-19 संकट से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई। 6 साल में किसानों की आय 20 से 68% तक बढ़ी।

किसान सम्मान निधि
के तहत प्रत्येक किसान परिवार को हर 6000 रु. डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। 10.19 करोड़ किसानों को सहायता दी।

नए कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को अब देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की सुविधा मिली। अनुबंधित खेती में पहली बार किसानों को सही कानूनी हक मिला। इसका सही लाभ देश के 86% छोटे किसानों को मिल रहा है।

सपने पूरे होने की उम्मीदें

स्टार्टअप को 3,67,175 लाख रु.का फंड
किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में 346 स्टार्टअप को 3,67,175 लाख रुपये का फंड दिया गया है इससे कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बल मिलेगा।

कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रा फंड की शुरुआत अगस्त 2020 की गई है। इस फंड के सहारे उद्योगों की तर्ज पर कृषि क्षेत्र से जुड़े आधारभूत ढांचे जैसे-वेयर हाउस, परिवहन व्यवस्था, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की व्यवस्था में सुधार आएगा।

किसान सम्मान निधि के तहत 10 सालों में 7 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाने हैं। अभी तक 94 हजार करोड़ रूपये ट्रांसफर किए भी जा चुके हैं।

कोरोना काल में में जहां देश के सभी सेक्टर मंदी से प्रभावित रहे वहीं सिर्फ कृषि सेक्टर में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पाद के साथ दोनों तिमाहियों में 3.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। ऐसे में नए साल में इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद हैं।

आधारभूत ढांचे के संबंध में किए गए सुधार गति पकड़ेंगे। मत्स्य पालन के क्षेत्र में आजादी के बाद सबसे बड़ी योजना लाकर इससे जुड़े लोगों की आय भी दोगुना करने की तैयारी है।

ऊर्जा का पॉवर हाउस बनता भारत

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एक देश, एक ग्रिड योजना का एलान किया था। केंद्र सरकार ने 2022 तक हर घर बिजली कनेक्शन और एकसमान बिजली का लक्ष्य भी तय किया। बिजली उत्पादन देश में लगातार बढ़ने के साथ मांग और आपूर्ति का अंतर भी घटा है। 2018-19 के बाद से लगातार तीसरे साल यह -1% से भी नीचे आ गया है। ये अंतर 2011-12 में 10.6 फीसदी रहा था। 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बिजली ट्रांमिशन क्षमता 1,18,050 मेगावाट करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड अब वास्तविकता बन रही है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

नया सवेरा

3,73,436 मेगावाट के राष्ट्रीय बिजली उत्पादन

अक्टूबर, 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 3,73,436 मेगावाट के राष्ट्रीय बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों की भागीदारी 89,636 मेगावाट है।

100 फीसदी गांव का विद्युतीकरण पूरा हुआ। 2014-15 में 1110.4 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो 2019-2020 में बढ़कर 1389.1 बिलियन यूनिट पहुंचा।

बिजली की मांग 2014-15 में करीब 10,68,923 मेगावाट थी जबकि पूर्ति 10,30,785 मेगावाट की रही। यानी जरूरत से 38,138 यूनिट कम।

पीक ऑवर में 1,77,019 मेगावाट की अधिकतम मांग रही, 1,76,413 मेगावाट की पूर्ति की गई। ये पीक ऑवर मांग और पूर्ति के बीच सबसे छोटा -605 मेगावाट का अंतर रहा है। यानी लोगों को जितनी जरूरत थी, उससे अधिक बिजली उपलब्धता रही है।

सौभाग्य योजना

2.5 करोड़ घरों का विद्युतीकरण। बिजली उपलब्धता में भारत की रैंकिंग 137 से सुधरकर 22 पर आई।

उजाला योजना

199 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। सालाना 24 करोड़ रु. की बचत।

नई उम्मीद

450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य

केंद्र सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट और 2035 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है (एक गीगावाट यानी 1000 मेगावाट)।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 3 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। इसमें सरकार सोलर सिस्टम से बिजली के लिए 5 एलईडी लाइट, एक डीसी पंखा, एक पॉवर प्लग देगी।

अक्षय ऊर्जा के अन्य घटक पवन, बायो, पनबिजली की परियोजनाओं पर भी मोदी सरकार की प्रतिबद्धता से यह स्पष्ट है कि 2035 से पहले भारत नवीकरणीय ऊर्जा के सभी लक्ष्य हासिल कर लेगा।

राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत सौर ऊर्जा उपकरण की स्वदेशी कंपनियों का बढ़ावा देकर वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य भी तय किया है।

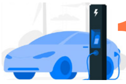

10,000 हजार ई-वाहनों की खरीद का लक्ष्य, इससे 136.37 बिलियन यूनिट बिजली बचत, 151.7 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

पीएम-कुसुम

महाअभियान योजना में गांव में निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए 22,750 मेगावाट बिजली उत्पादन की सौर क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य।

भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तीकरण

समाजसेवी और ग्रामीण स्वावलंबन के लिए प्रसिद्ध भारतरत्न नानाजी देखमुख ने कहा था, "जब तक गांव के लोग विवादों में उलझे रहेंगे, तो न तो वे खुद को विकसित कर पाएंगे और न ही समाज को।" इसी को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 'मेरी संपत्ति, मेरा हक' वाले पीएम स्वामित्व योजना शुरू की है। ग्रामीण आबादी वाली इन संपत्तियों पर छह दशक से ध्यान नहीं दिया गया, जिससे संपत्ति विवाद लगातार बढ़ रहे थे। ये योजना न सिर्फ दबंगों को ग्रामीणों की जमीन कब्जाने से रोकेगा बल्कि कोर्ट कचहरी में पूर्वजों की जमीन का मालिकाना हक साबित करने में मदद करेगी।

नया सवेरा

अप्रैल, 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना में गांव की हर आवासीय प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा ड्रोन से पैमाने पर पूरी पैमाइश के साथ दर्ज होगा। अंग्रेजी शासनकाल के समय से ऐसी संपत्तियों का रिकॉर्ड नहीं रखा गया।

- परिवार को प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में मालिकाना हक साबित करने में दिक्कत नहीं होगी, मकान बनाने या खरीदने का लोन आसानी से मिलेगा।
- सरकारी पंजीकरण से प्रॉपर्टी की कीमत तय करने में होगी आसानी। नकली कागज पर कोई दबंग निम्न वर्ग के व्यक्ति की संपत्ति नहीं बेच पाएगा। एक लाख से अधिक संपत्तियों की जियो टैगिंग हुई।
- पायलट प्रोजेक्ट के चरण में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के 763 गांव में 1 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण करके लाभार्थियों को मालिकाना हक वाला संपत्ति कार्ड कोरोना काल में दिया गया।
- स्वामित्व योजना से भूमि का रिकॉर्ड अब घर बैठे देख सकेंगे और प्रिंट भी ले सकेंगे।
- वक्फ बोर्ड और अन्य बड़ी संपत्ति का विवाद भी खत्म हो जाएगा।
- सरकारें या स्थानीय निकाय इन संपत्ति का सर्किल रेट तय कर सकेंगी।

नई उम्मीदें

- संपत्ति के डिजिटलाइजेशन की शुरूआत स्वामित्व योजना के तहत कोरोना काल में हुई है, लेकिन आने वाले साल में अब पूरे देश में डिजिटलाइजेशन होगा।
- पंजाब और राजस्थान में 101 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन (CORS) लगाए जा रहे हैं। देश भर में 300 स्टेशन बनेंगे। किसी स्थान का सटीक निर्धारण इससे हो सकेगा, पुनः सर्वेक्षण में सुविधा रहेगी।
- चालू वित्त वर्ष में सर्वेक्षण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाकर करीब 50 लाख संपत्ति धारकों को जमीन का मालिकाना हक कार्ड देने का लक्ष्य।
- बिचौलिए खत्म होंगे तो गरीबों को पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन हस्तांतरण की राह होगी आसान। गांव विकास में स्वामित्व योजना सहायक होगी। अप्रैल, 2024 तक सभी 6.62 लाख गांवों को स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण में कवर किया जाएगा। फिर स्वामित्व कार्ड मिलेगा।
- ग्रामीण संपत्ति का नामांकरण आसान हो जाएगा। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर संपत्ति डिजिटलीकरण और उससे जुड़ी जानकारी मिलेगी और वहीं जमीन का स्टेटस भी देख सकेंगे।
- गांव में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं कहां होंगी, इसका फैसला सबकी नजर में संबंधित काम के लिए खाली जमीन के हिसाब से होगा।

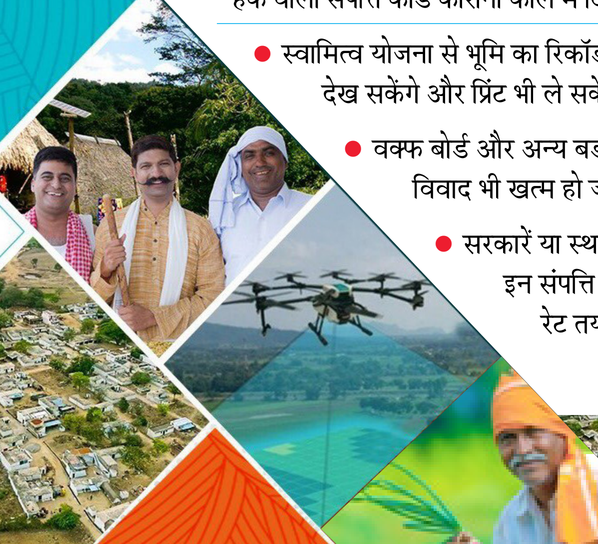
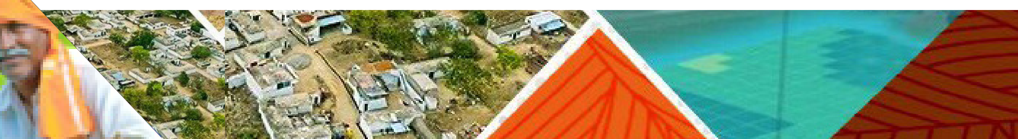

शिक्षा का ग्लोबल हब बनेगा भारत

इक्कीसवीं सदी भारत की हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिश्रम से जुटने का आह्वान किया है। इस लक्ष्य को साधने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मदद करेगी। प्रधानमंत्री कहते हैं "यह नीति तेजी से बदलती दुनिया में हमारे युवाओं को भविष्य के लिए ज्ञान और कौशल से मजबूत करके भारत को आत्म-निर्भर बनाने वाली है। इस नीति का लक्ष्य 21वीं सदी में भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है।" यह नीति देश के भीतर ही विश्व स्तरीय शोध सुविधाएं, अवसर प्रदान कर 'भारत में अध्ययन' और 'भारत में निवास' की स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना को साकार करने में मदद करेगी।

नया सवेरा

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तय भावना के हिसाब से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है।
- नई शिक्षा नीति में पुराने 10+2 के ढांचे में बदलाव करके 5+3+3+4 के एक नए पाठयक्रम ढांचा तय किया गया है। जो क्रमशः 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष के बच्चों के लिए है।
- स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की दृष्टि के हिसाब से 5वीं तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा में, 8वीं या उससे आगे तक भी प्राप्त की जा सकती है। तकनीकी शिक्षा मातृभाषा में कराने का रोडमैप तैयार को एक कार्यबल गठित।

नई शिक्षा नीति में इनका योगदान

2,50,000 ग्राम पंचायत

12,500 स्थानीय निकाय

675 | जिलों की व्यापक भागीदारी

15,00,000 शिक्षकों के सुझावों पर मंथन से तैयार।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के हिसाब से दो करोड़ ड्रॉपआउट स्कूलों में लौटेंगे। नीति में केंद्र और राज्य सरकार सकल घरेलू उत्पाद का करीब 6 फीसदी निवेश पर एक साथ काम करेगी।
- पेटेंट कराने की जागरुकता को लेकर 'कपिला' कलाम कार्यक्रम शुरू।

नई उम्मीदें

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रो. के. कस्तूरीरंगन ने कहा, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में उसकी आबादी के रूप में उपलब्ध लाभकारी संसाधनों का पूंजीकरण कर चौथी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात-जी.ई.आर. को वर्ष 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है
- मूल्यांकन प्रणाली में समग्र सुधार के लिए नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र 'परख' की स्थापना की जाएगी।
- भारतीय सूचना प्राद्योगिकी कानून(संशोधन) विधेयक, 2020 संसद के दोनो सदनों से पारित। इससे सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर के आईआईआईटी को सार्वजनिक निजी भागीदारी(पीपीपी) मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जाएगा।
- प्रारंभिक शिक्षा और बचपन में देखभाल के लिए एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगी।
- शिक्षा मंत्रालय साक्षरता और राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रीय मिशन गठित करेगा। शिक्षा में प्रोद्योगिकी प्रयोग बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रोद्योगिकी मंच बनेगा। वंचित क्षेत्र व समूहों के लिए लिंग समावेशी निधि व विशेष शिक्षा जोन स्थापित होंगे ।
- छठी कक्षा से व्यवायिक शिक्षा, इंटर्नशिप भी शामिल होगी। संस्कृत भाषा की पढ़ाई करने का विकल्प उच्चशिक्षा में भी दिया जाएगा।

आपकी जीवनशैली अब आयुर्वेदिक

अलग से आयुष विभाग का मंत्रालय बनाकर 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकृत करने का प्रयास किया। भारत के प्रयासों की वजह से दुनिया में 21 जून 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। उसी का नतीजा है कि अचानक आई कोरोना जैसी महामारी में आयुर्वेद-योग ने देश की रक्षा की तो दुनिया को भी इस प्राचीन परंपरा की ताकत का अहसास कराया। समग्रता में स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने वाले आयुर्वेद का बाजार अब देश-दुनिया में तेजी से बढ़ रहा तो भारत अपनी सभ्यता की इस पहचान का प्रणेता बनने को है तैयार

> “ आयुर्वेद भारत की एक विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है। ये देखकर किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है।

आयुर्वेद की बढ़ती महत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के काल में और भी अहम साबित हुआ है। कोरोना की कोई दवाई नहीं होने की वजह से आयुर्वेद और योग ही एक ऐसा माध्यम बना जिससे लोगों ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढाया और इस महामारी से बचाव किया। आधुनिक चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि कोरोना का बचाव अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। यही वजह है कि कोरोना के इस काल में दुनिया की निगाहें भारत के आयुर्वेद और योग की परंपरा पर टिकी रही। दुनिया के देश भी अब आयुर्वेद की शक्ति को स्वीकारने लगे हैं। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या अब आयुर्वेद दवाई की पुड़िया के संकुचित नजरिए से बाहर निकलने को है? इसका जवाब निश्चित तौर से हां में होगा क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीन पद्धति की ओर न सिर्फ लोगों का रूझान बढ़ा है बल्कि आयुर्वेद ने भी आधुनिकता के साथ तालमेल कर पांव पसारना शुरू कर दिया है।

आयुर्वेद बन रहा जीवन का अंग

आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा, जहां आयुर्वेद से जुड़ा एकाध उत्पादन मौजूद नहीं हो। अंग्रेजी दवाओं के दुष्प्रभाव (साइड इफेक्टस) की आशंका के मद्देनजर लोग सौंदर्य प्रसाधन से लेकर भोजन तक में हर्बल उत्पाद का प्रयोग करने लगे हैं। अनियमित जीवन शैली से परेशान लोगों के जीवन में आयुर्वेद एक आवश्यक अंग बन गया है।

आठ शाखाओं में बंटी है आयुर्वेद चिकित्सा

आयुर्वेद को लेकर लंबे समय तक मिथक भी रहा है और इसे एलोपैथी

आयुर्वेद में क्या है खास

प्राचीन चिकित्सा पद्धति अब आधुनिकता के साथ कदमताल कर रही है तो लोगों का भी ध्यान, साधना से लेकर चिकित्सा तक का आकर्षक पैकेज मुहैया करा रही है।

पर्यटन

अनियमित जीवनशैली की वजह से होने वाली बीमारियों के साथ मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग, साधना और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में केरल, बेंगलुरू, हरिद्वार, ऋषिकेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र आयुर्वेद के क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनकर उभरे हैं।

पंचकर्म

शरीर में नित्य क्रिया क्रम के जरिए होने वाली साफ-सफाई के बावजूद विषैले तत्व उसी तरह जमा रह जाते हैं, जैसे पानी की टंकी में गाद। ऐसे में पंचकर्म ऐसी पद्धति है जिसमें वमन, विरेचन, नस्य, वस्ती और रक्तमोक्षण की क्रियाएं हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे क्रोमोजोम स्तर तक की सफाई हो जाती है।

सुविधाएं

आयुर्वेद से जुड़े अस्पतालों और दवाई दुकानों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ी है। दिल्ली में ही एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान 2016 से आधुनिक सुविधाओं के साथ शोध पर काम कर रहा है।

बाजार

दुनिया के आयुर्वेद बाजार में भारत की स्थिति 2014 से पहले बहुत मजबूत नहीं थी। जबकि इसका वैश्विक बाजार अनुमानित तौर पर 80 अरब अमेरिकी डॉलर का है जिसका 2050 तक 6 खरब होने का अनुमान है। ऐसे में इस प्राचीन सभ्यता का अगुवा भारत के सामने सुनहरा अवसर है।

जग रही उम्मीद

आयुर्वेद की महत्ता को इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है। 2015 की जुलाई में अफगानिस्तान से आए तब 8 वर्षीय मो. मूसा की गर्दन अपने सहारे नहीं टिक पाती थी। अफगानिस्तान और भारत के बड़े अस्पतालों में उसका ईलाज नहीं हो पाया तो उसके पिता यूसुफ नईमी ने आयुर्वेद का सहारा लिया। महज छह महीने के आयुर्वेदिक इलाज से मूसा जो दो मिनट भी खड़े होकर काम नहीं कर पाता था, करीब 6-8 मिनट काम करने लगा।

के प्रतिस्पर्धी व्यवस्था के तौर पर पेश करते हुए कमतर दिखाया जाता रहा है। लेकिन सही मायने में यह एलोपैथी का सहायक है। एलोपैथी त्वरित राहत देता है तो आयुर्वेद की प्रक्रिया रोगों को जड़ से खत्म करने का काम करती है। सर्जरी से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के ग्रंथों में दर्ज है। 1,000 ई.पू. में ही आयुर्वेद चिकित्सा को आठ खंडों में बांटा गया था। इनमें काय चिकित्सा (मेडिसीन), बाल चिकित्सा, मानस रोग (न्यूरोलॉजी), शल्य चिकित्सा (सर्जरी), शालक्य चिकित्सा (ईएनटी-दांत), अगद तंत्र (टॉक्सिकोलॉजी), रसायन चिकित्सा और वृष्य चिकित्सा (अगली पीढ़ी को स्वस्थ रखना) शामिल है। दादी-नानी की पिटारी और रसोई घर में साधारण बीमारियों से निपटने का नुस्खा आयुर्वेद ने दिया है, लेकिन इतना व्यापक होकर भी आयुर्वेद लंबे समय तक भारत में इतना क्यों पिछड़ गया? 11वीं-12वीं सदी में बाहरी हमलों ने इसे नुकसान पहुंचाया और ब्रिटिश राज में 1835 में आयुर्वेद पर सीधा हमला हुआ। तब कोलकाता में आयुर्वेद कॉलेज को बंद कर उसे आधुनिक मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। वैद्यों को अप्रशिक्षित बताया गया और अंग्रेजों ने कानून लाकर एलोपैथी को अनिवार्य करते हुए आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा को बाहर कर दिया।

देश में योग-आयुर्वेद का आधिकारिक सफर

आजादी के दो दशक बाद 1970 में कानून के जरिए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध के चिकित्सकों को कानूनी संरक्षण मिला। पहली बार 1995 में इसे अलग विभाग बनाया गया और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय इसे आयुष नाम दिया गया। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने आयुष का अलग मंत्रालय बनाकर आयुर्वेद और योग को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने का जिम्मा उठाया। प्रधानमंत्री बनने के चार महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल संयुक्त राष्ट्र के मंच से की और 11 दिसंबर को को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों और 177 सह समर्थक देशों ने 21 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मिति से स्वीकार कर लिया। उसके बाद से हर साल 21 जून को इसका आयोजन हो रहा है।

बदलती तस्वीर

- बीते छह साल में आयुष कॉलेजों की संख्या 200 के करीब बढ़कर अब 711 तक पहुंची।
- 435 नए आयुष अस्पताल खुले और अब भारत में इसकी संख्या 4035 हुई।
- 1821 नए आयुष डिस्पेंसरी स्थापित हुए 2014 से 2018 के बीच, और अब देश में कुल 27951 स्थापित हो चुके हैं।
- आयुष प्रैक्टिशनर्स की संख्या अब 8 लाख तक पहुंची।
- करीब 18 करोड़ मरीजों ने आयुष के तहत दी गई सुविधा का लाभ उठाया।
- देश में आयुष के तहत करीब 9 हजार लाइसेंस प्राप्त दवाई दुकानें उपलब्ध है।

कोरोना टीकाकरण

- पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस समय जिस सबसे बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वह है कोरोना वैक्सीन। भारत में भी जायडस कैडिला की जायकोव डी, भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सिन के साथ सीरम इंस्टीट्यूट कोवीशील्ड का ट्रायल चल रहा है।
- नए साल में जल्द ही हमें वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन के परिवहन, स्टोरेज से लेकर टीकाकरण और उसके अलग-अलग चरणों के हिसाब से पूरी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।
- डॉ. वीके पाल के नेतृत्व में नेशनल वैक्सीन कमेटी ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ऐसे 31 करोड़ लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें मार्च से मई के बीच वैक्सीन दी जाएगी।

प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना

- देश के 700 से ज्यादा जिलों में मौजूद 6600 से ज्यादा प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र आज लोगों को 90 फीसदी तक सस्ती दरों पर दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। इन केंद्रों पर 1250 दवाईयां और 204 सर्जरी के उपकरण मौजूद हैं। महिला स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार अब इन जनऔषधि केंद्रों पर 1 रुपये में सैनेटरी नैपकिन भी उपलब्ध करा रही है।

ब्राजील के राष्ट्रपति ने हनुमान कहा और 150 से अधिक देशों को सप्लाई

कोविड काल में भारत ने जब ब्राजील को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा उपलब्ध कराई तो वहां के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो ने इसकी तुलना हनुमानजी द्वारा लक्ष्मणजी के लिए संजीवनी बूटी लाने से की।

प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवसः 21 जून 2015 को नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजन हुआ। इसमें 35,985 प्रतिभागियों के साथ बड़ा योग सत्र और एक ही योग अभ्यास सत्र में सर्वाधिक 84 देशों के नागरिकों की प्रतिभागिता की वजह से दो गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बने।

आयुष्मान भारत

दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर स्कीम के साथ भारत ने यूनीवर्सल हेल्थकेयर की दिशा में कदम तेजी से बढ़ाया। इसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रु. तक की मुफ्त इलाज सुविधा दी गई है। भारत में पहली बार केंद्र की किसी सरकार की ओर से स्वास्थ्य को इतने बड़े पैमाने पर प्राथमिकता दी गई।

स्वास्थ्य क्षेत्र बना रोजगार का बड़ा अवसर

देश के लोगों की स्वास्थ्य की फिक्र के साथ-साथ केंद्र सरकार की पहल से रेलवे के बाद स्वास्थ्य दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र बनकर उभर रहा है। कोरोना आपदा के समय भारत ने अपनी क्षमता का परिचय दिया और पीपीई किट के उत्पादन में भारत शून्य से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर चंद महीनों में उभरा है। इसी तरह एन-95 मास्क के उत्पादन में भी भारत ने मिसाल कायम की है।

नई उम्मीदें

- इस साल कोरोना वैक्सीन की उम्मीद है जो संभवतया स्वदेशी होगी और इतने विशाल देश में हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली है।
- केंद्र सरकार ने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता भी दे दी है। इससे लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ेगी।
- योगासन को खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। योगासन की खेल प्रतियोगिताओं के लिए 4 स्पर्धाओं, 7 श्रेणियों में 51 पदक प्रस्तावित किए जा सकते हैं। यूनीवर्सल हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ेगा।
- सस्ती और अच्छी दवाई के लिए जन औषधि केंद्र में देश के सारे जिले होंगे कवर। महिलाओं को सैनेटरी पैड 1 रु. में उपलब्ध है, जिसका विस्तार होगा।

जय जवान, जय किसान के साथ अब जय विज्ञान, जय अनुसंधान

'तकनीक प्रथम' का मंत्र लेकर आगे बढ़ रही केंद्र सरकार देश के हर गांव को हाईस्पीड ऑप्टिकल फाइबर वाले इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ रही है। वर्ष 2014 के पहले जहां सिर्फ पांच दर्जन पंचायतों तक इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की पहुंच थी, अब यह डेढ़ लाख से अधिक पंचायतों तक पहुंच चुका है। तो वहीं नए साल में हर दिन 600 गांव इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है। यही नहीं 6 साल में इंटरनेट भारत में 56 गुणा तक सस्ता हुआ तो अब अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्ट अप इंडिया जैसे कार्यक्रम की बदौलत इनोवेशन के मामले में आगे बढ़ रहा है भारत...

इंटरनेट

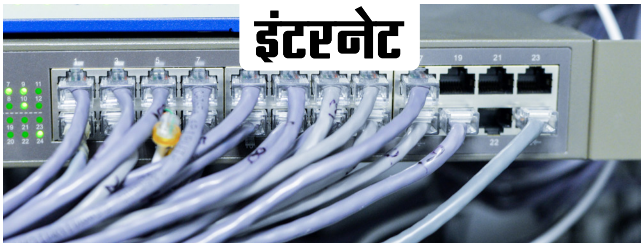

नया सवेरा

- भारत नेट परियोजना के तहत डेढ़ लाख पंचायतें पांच साल में ऑप्टिकल फाइबर वाले इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी हैं।
- गांव में इंटरनेट की खपत शहरों के मुकाबले ज्यादा हुई। छह साल में भारत में इंटरनेट 56 गुणा सस्ता हुआ।
- कारोबार में जीएसटी सहित ई-चालान एक महीने में सबसे अधिक 641 लाख बनाए गए।
- उमंग एप के जरिए 2039 सुविधाएं सिर्फ एक क्लिक पर मौजूद हैं। देश के 5682 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा।

नई उम्मीदें

- नए साल में हर दिन 600 गांव हाईस्पीड वाले इंटरनेट के फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे। यानी नए साल में करीब 2.19 लाख नए गांव तक ये हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन पहुंच जाएगा।
- प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सरकार ने पहले सिर्फ ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था अब बची हुई 80 हजार से अधिक पंचायतों के साथ गांव में भी इंटरनेट का फाइबर नेटवर्क पहुंचेगा।
- एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023 तक इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़कर 83.50 करोड़ होने की संभावना है।

इनोवेशन

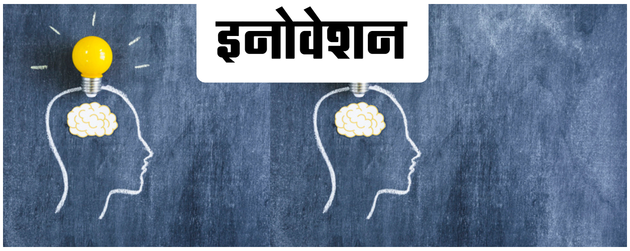

जिन उम्मीदों को छुआ...

- स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों की बदौलत भारत पहली बार इनोवेशन के मामले में दुनिया के टॉप 50 देशों में शामिल। 2015 में यह रैंकिंग 81 थी। 2020 में रैंकिंग 48 पहुंची।
- स्कूल से ही बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई। 4 लाख बच्चे प्रशिक्षित हुए।
- ऑटो से भी कम किराये में हमारा मंगलयान मंगल ग्रह तक पहुंचा। अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल की।

अब पूरी होंगी ये उम्मीदें...

- डिजिटल इंडिया में गूगल 10 सालों में 75 हजार करोड़ रु. का निवेश करेगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष कार्यनीति के तहत काम, अगले 15 सालों में 7 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष कार्ययोजना।
- भारत में 10 हजार अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का लक्ष्य। इस साल 5400 टिंकरिंग लैब खोली जाएंगी।
- अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा गगनयान मिशन को मंजूरी दी गई है।

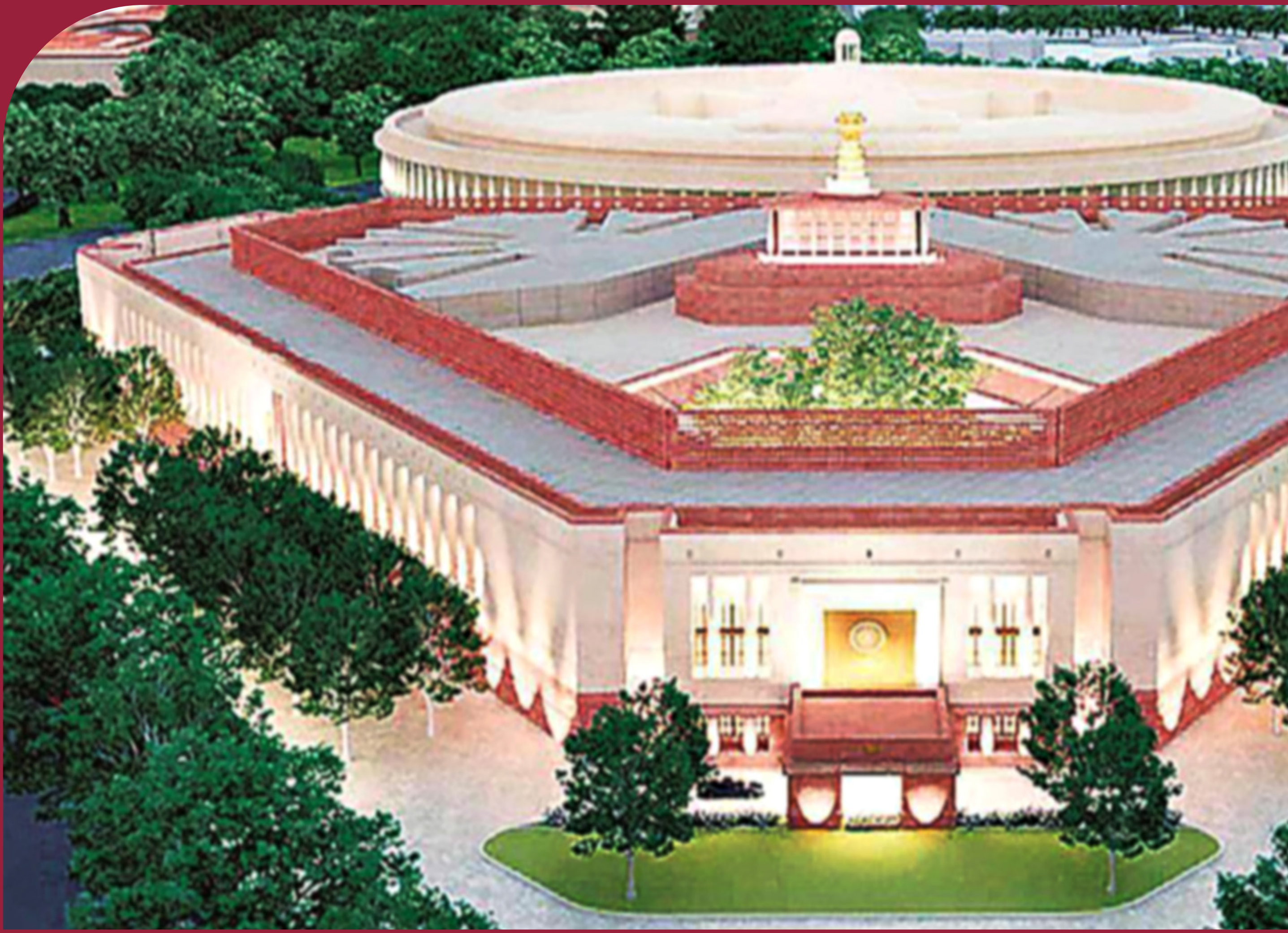

लोकतंत्र का नया मंदिर

नए संसद भवन का भूमि पूजन

“पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

संसद मार्ग पर 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के लिए भूमि पूजन किया। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से तीन गुना ज्यादा होगा। राज्यसभा का भी आकार बढ़ेगा। नए भवन की साज-सज्जा में भारतीय संस्कृति, शिल्प और वास्तुकला, क्षेत्रीय कला की विविधता का मिलाजुला रूप होगा। डिजाइन योजना में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है।

इस योजना को तीन चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर के दायरे में मौजूद 'सेंट्रल विस्टा क्षेत्र' को 2021 तक नया रूप दिया जाना है। जबकि मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक संसद भवन की नयी इमारत का निर्माण 2022 तक और तीसरे चरण में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को एक ही स्थान पर समेकित करने के लिये प्रस्तावित समग्र केन्द्रीय सचिवालय का निर्माण 2024 तक करने का लक्ष्य है।

उम्मीदों का अर्थ सपनों की व्यवस्था

पहली ईस्वी से 2000 ईस्वी के बीच साढ़े सत्रह सौ साल तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में अकेला एक तिहाई योगदान देने वाले भारत की अर्थव्यवस्था आजादी के 7 दशक बाद भी सिर्फ 3 ट्रिलियन तक पहुंच पाई थी। वर्ष 2014 के बाद देश के आम आदमी के जीवन स्तर से लेकर आर्थिक मोर्चे पर हुए अहम सुधारों का नतीजा है कि भारत अब 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के सफर पर चल रहा है। 'भारत प्रथम' के सिद्धांत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को आज उन तमाम रिफॉर्म्स यानी सुधारों की वजह से पंख लग पाए हैं, जिनका हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। एक देश, एक टैक्स के साथ जीएसटी की व्यवस्था, 100 साल में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, कालेधन की वापसी के लिए नोटबंदी, टैक्स सुधार, व्यापार के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे कदमों का असर है कि आज दुनिया का भरोसा भारत में बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत विदेशी निवेश में जोरदार बढ़त इसके सबूत हैं। यही नहीं, कोरोना काल में जब भारत के सामने चुनौती आई तो 'जान है तो

वित्तीय सुरक्षा के साथ नया सवेरा

जनधनः 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का खाता खुला

प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2015 को हुई थी। केंद्र सरकार की यह योजना देश में आर्थिक सुधारों की नींव रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज किया गया है।

40.38

करोड़ से अधिक खाते खोले

जनधन योजना के तहत पहली बार ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले गए जिनका अभी तक कोई खाता नहीं था। अभी तक 41 करोड़ 38 लाख खाते खोले।

₹130,932,33

करोड़ रुपये जमा हैं जनधन खातों में। कोरोना काल में इन्हीं खातों के माध्यम से 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणः 100 में से 100 पैसे गरीब को

₹13,23,778

करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में

वर्ष 2014 से अब तक इसके माध्यम से 13 लाख 23 हजार 778 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। डीबीटी के माध्यम से अब आम आदमी तक उसके हक का पूरा पैसा पहुंच रहा है।

- एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से आम आदमी की मदद के लिए चलने वाला 1 रुपया उन तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत गरीबों तक उनका पूरा हक पहुंचाने के लिए की गई थी।
- डीबीटी योजना के जरिए भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर रोक लगी है। 51 मंत्रालयों की 325 योजनाओं इससे जोड़ी जा चुकी हैं। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को अभी तक 1 लाख 78 हजार 396 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

जीएसटीः अब एक देश-एक कर

वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) को 101वें संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया। जीएसटी का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि 30 जून 2017 की आधी रात को संसद सत्र बुलाकर भारत की आर्थिक एकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए एक देश-एक कर के नारे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी।

इससे पहले 14-15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, 14-15 अगस्त, 1972 में भी देश की स्वतंत्रता के 25 वर्षों का जश्न मनाने के , 9 अगस्त, 1992 को भी भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने पर और 14-15 अगस्त, 1997 को भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आधी रात को संसद का सत्र हुआ था।

कई लोगों ने आधी रात को सत्र बुलाने पर प्रश्न उठाया लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि यह केंद्र सरकार पुराने ढर्रे ओर परिपाटी को बदलने के लिए ही काम कर रही है।

जीएसटी कानून से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही उत्पाद पर कर की दरें अलग-अलग होती थीं। इससे निर्माताओं और खरीदार दोनों में भ्रम रहता था। इस लिहाज से देश के आर्थिक एकीकरण की दिशा में जीएसटी सबसे क्रांतिकारी कदम है।

भारत में जीवन के लिए जरूरी वस्तुओं से लेकर विलासिता वाली वस्तुओं तक कर की अलग-अलग चार दर 5,12,18 और 28 प्रतिशत तक रखी गई है।

जहान है' के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लेकर महामारी से लड़ने का मुकम्मल रास्ता तैयार किया, फिर 'जान भी जहान भी' की नीति के साथ देश को अनलॉक कर कारगर उपायों पर काम शुरू किए। इसी का असर है कि कोरोना काल में बेहद नीचे जा पहुंची अर्थव्यवस्था की तरक्की की रफ्तार अनलॉक के बाद 'वी आकार' में रही है।

आर्थिक मोर्चे के साथ देश के आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार और ऐसी समस्याओं की ओर केंद्र सरकार ने लगातार ध्यान दिया है, जिनके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं गया था। उदाहरण के तौर प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण के उस अंश पर ध्यान दीजिए जब उन्होंने कहा था- "हमारा देश कैसे-कैसे कमाल करता है, कैसे-कैसे आगे बढ़ता है, इस बात को हम भली-भांति समझ सकते हैं। कौन सोच सकता था कि कभी गरीबों के जनधन खाते में लाखों-करोड़ों रुपये सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे।" कोरोना काल में इन जनधन खातों के जरिए ही केंद्र सरकार सीधे आम आदमी तक मदद पहुंचाने में कामयाब रही। वहीं मध्यम वर्ग को राहत देने वाले टैक्स सुधार की वजह से जहां टैक्स संग्रह में वृद्धि हुई तो भारत फेसलेस असेसमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है।

कॉरपोरेट टैक्स
कंपनियों पर बोझ कम

पहले घरेलू कंपनियों को 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता था। इसके अलावा सरचार्ज अलग से। अब इसे घटाकर 22% कर दिया गया। प्रभावी दर के साथ सरचार्ज और सेस के साथ यह 25.17 फीसदी है। इससे पहले भारत में कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इससे व्यापार को सीधा फायदा होगा। विनिर्माण इकाइयों को फायदा होने से निवेश के साथ रोजगार की नई संभावना पैदा होंगी।

इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी
देनदारों पर सख्ती, घटा एनपीए

जब कोई देनदार कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसके द्वारा लिया गया कर्ज को नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) कहा जाता है। किसी कारोबारी द्वारा बैंकों का कर्ज़ चुकता न किये जाने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इससे निबटने के लिए सरकार ने वर्ष 2016 में दिवालिया कानून (इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड) लागू किया था। नए कानून की वजह से एनपीए घटकर 9% से कम पर आ गया।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
कारोबारी सुगमता में आगे

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत ने जबरदस्त छलांग लगाई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 14 पायदान चढ़कर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत इस सूची में 77वें नंबर पर आ गया था। दुनिया के हर देश में कारोबार की सुगमता को इस पैमाने के जरिए ही देखा जाता है।

नोटबंदी: अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता के लिए क्रांतिकारी कदम

- भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 8 नवंबर 2016 को लिया गया नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण का फैसला न सिर्फ देश की प्रगति का आधार बना है बल्कि कालाधन को कम करने और पारदर्शिता लाने में क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है।
- नोटबंदी से ईमानदार संस्कृति को बढ़ावा मिला और आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 4 करोड़ से बढ़ 6.79 करोड़ हुई।
- 2014-15 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 695792 करोड़ से बढ़कर 1050678 करोड़ रु. हुआ। 3 लाख करोड़ रु. बैंकिंग सिस्टम में वापस।

विदेशी निवेश: नए रिकॉर्ड पर भारत

- केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का भारत में कारोबारी सुगमता के लिए उठाए गए कदमों का असर है कि पिछले 5 सालों में विदेशी निवेश में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।
- 2008-14 में 231.37 अरब डॉलर की तुलना में 2014-20 में विदेशी निवेश प्रवाह में 55 फीसदी की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में विदेशी निवेश हासिल करने वाले देशों में भारत का नौवां स्थान था।
- कोरोना संकट के बावजूद 2020-21 के अप्रैल-अगस्त में 27.1 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में विदेशी निवेश से यह 16 फीसदी ज्यादा है।

नई उम्मीदें

- केंद्र सरकार ने जीएसटी सिस्टम को को लचीला बनाकर राहत देने के लिए लगातार पहल की हैं। पहले जो औसत टैक्स दर 14.4% थी वह अब 11.8% है।
- इसे और लचीला बनाने का प्रयास लगातार जारी है। इस सिलसिले में जीएसटी काउंसिल की अभी तक 13 बैठकें हो चुकी हैं।
- सुधारों का ही असर है कि कोरोना काल में अनलॉक के बाद अक्टूबर और नवंबर महीनों में लगातार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है।
- टैक्स सुधार के बाद भारत में आयकर रिटर्न दायर करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर किए गए नए सुधारों के बाद अब आयकर दाता की किसी भी शिकायत का निराकरण फौरन करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ अब फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत हुई है।
- जनधन योजना के तहत दिसंबर तक 41 करोड़ 38 लाख से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं।
- जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब लक्ष्य था हर परिवार में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता हो। इससे आगे बढ़कर अब परिवार के हर वयस्क सदस्य का बैंक खाता खोलने का लक्ष्य तय।

आस्था का केंद्र श्री काशी विश्वनाथ भव्य रूप में 2021 में लेगा आकार

आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तीर्थ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदु आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। अब मां गंगा और काशी विश्वनाथ को जोड़ने के संकल्प की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस परियोजना के जरिए आसपास के क्षेत्र ही नहीं, वाराणसी का कायाकल्प हो रहा है। इस आस्था की परंपरा को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जिनकी प्रेरणा से मंदिर भव्य रूप ले रहा है। बाबा विश्वनाथ को मां गंगा से जोड़ने का संकल्प साकार करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। करीब 50,261 वर्ग मीटर विस्तृत क्षेत्रफल की इस परियोजना में कुल 24 भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना पर काम कर रही है, जिसका 28 फीसदी काम पूरा हो चुका है। श्री काशी विश्वनाथ धाम को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश के दैदीप्यमान प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा।

आधुनिकीकरण

- **परियोजना क्षेत्र में स्थित लगभग 63 छोटे-बड़े मंदिरों जिसमें मुख्य रूप से पांच पांडव, गंगेश्वर महादेव, मनोकामेश्वर, नीलकंठ महादेव, द्वादश लिंग और अन्य मंदिरों की पुनर्स्थापना और संरक्षण व परिसर में स्थित गोयनका लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।**
- **परियोजना में चिन्हित 314 भवनों के प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वासन किया गया है।**
- **इस परियोजना का मुख्य आकर्षण मंदिर परिसर है जिसका क्षेत्रफल 3175 वर्ग मीटर है।**
- **इसके साथ ही मंदिर चौक, सिटी म्युजियम, वाराणसी गैलरी, बहुद्देशीय भवन, पर्यटक सुविधा केंद्र, मुमुक्षु (मोक्ष की कामना करने वाला) भवन, गेस्ट हाउस, नीलकंठ मंडप, सुरक्षा कार्यालय, यात्री सुविधा केंद्र, भोगशाला, आधुनिक बुक स्टोर, जलपान केंद्र, यज्ञ-हवन के लिए वैदिक केंद्र की स्थापना दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है।**
- **वर्तमान समय में 28 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना के कार्य में करीब 1500 कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।**

आपका पासपोर्ट आपकी ताकत

बड़े फैसला लेना और उन्हें अंजाम तक पहुंचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का पर्याय बन चुका है। यही कारण है कि बीते 6 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए तैयार योजनाएं न सिर्फ हकीकत के धरातल पर उतरी हैं, बल्कि वे समय पर पूरी भी हो रही हैं। वो तमाम बदलाव और सुधार, जिनकी दरकार देश को वर्षों से थी। वर्षों से चलते पुराने ढर्रे को बदलकर शासन व्यवस्था को जनकेंद्रित बनाने का असर अब हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इसकी गवाही दुनियाभर के वो सूचकांक या इंडेक्स भी दे रहे हैं, जहां अभी तक रैंकिंग के मामले में भारत बहुत पीछे था।

ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म के मंत्र के आम आदमी के जीवन को आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार पहल कर रही है। पारदर्शिता के साथ सहूलियत के लिए सार्वजनिक सेवाओं में ई-गवर्नेंस को अधिक महत्व दिया गया है। इसी क्रम में भारतीय पासपोर्ट सेवा को आम जन के लिए और आसान व सुगम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में- "सरकार ने देश की साख बढ़ाने, सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आपका जीवन आसान बनाने का भी लगातार प्रयास किया है, इसका एक उदाहरण है- पासपोर्ट। पासपोर्ट और वीजा जैसी सुविधाओं के लिए बीते पांच वर्षों में देश में 300 से भी ज्यादा नए पासपोर्ट केंद्रों की भी स्थापना की गई है। बीते पांच वर्ष में, भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। जो भी दुनिया के किसी देश में जाता होगा, दुनिया के किसी भी देश में जब वो अपना हिंदुस्तान का पासपोर्ट दिखाता है तो सामने वाला हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। हिंदुस्तानी के प्रति गर्व से देखा जाता है।"

- बीते 6 वर्षों में पासपोर्ट सेवा को जनकेंद्रित और आसान बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2014 के पहले देश में जहां सिर्फ 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र चालू थे, वहीं अब 424

"पहले लोग कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता। उनकी सरकार ने इस सोच को ही बदल डाला है। दुनिया आज भारत की बात और सुझावों को पूरी गंभीरता से सुन भी रही है और समझ भी रही है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री (15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में)

भारत में जागा दुनिया का भरोसा

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

63 रैंक

ईज ऑफ डूइंग बिजेनस यानी कारोबारी सुगमता की रैंकिंग में भारत ने जबरदस्त छलांग लगाई है। वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत 14 पायदान चढ़कर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। 5 साल में 79 पायदान का सुधार।

विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा

48 रैंक

डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नतीजा है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। भारत अब 48 वें स्थान पर है। भारत में युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स

52 रैंक

दुनियाभर में इनोवेशन के मामले में भारत की रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 की सूची में भारत 52वें नंबर पर पहुंच गया है, पिछले साल भारत 57वें नंबर पर था। 2015 में भारत 81वें स्थान पर था।

प्रतिस्पर्धा रैंकिंग

43 रैंक

आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धिता रैंकिंग 2020 में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है इस रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धिता रैंकिंग के अनुसार भारत 2019 में भी 43वें स्थान पर ही था।

ईज ऑफ ट्रैवल

85 रैंक

ईज ऑफ ट्रैवल रैंकिंग के मामले में भारत का 85वां नंबर है। भारत ने 2020 के लिए जारी की गई हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां स्थान हासिल किया है। वहीं, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में 48वीं है। वर्ष 2019 में यह रैंकिंग 71 थी।

ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स

74 रैंक

भारत ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में दो पायदान ऊपर चढ़कर 74 वें स्थान पर आ गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने ऊर्जा सुधार की दिशा में सराहनीय कार्य किए हैं। आने वाले दिनों में भारत इस क्षेत्र में और तेजी से विकास करेगा।

भरोसेमंद देशों में शामिल

2 रैंक

भारत कारोबार, सरकार, एनजीओ और मीडिया के मामले में विश्व के सबसे भरोसेमंद देशों में शामिल है। 'एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर-2020' रिपोर्ट के अनुसार आबादी के बड़े हिस्से के बीच भरोसे के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।

ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस

02 रैंक

भारत वैश्विक उपभोक्ता विश्वास (ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस) 2020 सर्वे में दूसरे पायदान पर है। इससे पहले लगातार दो सर्वे में भारत टॉप पर रहा है। कोरोना काल में भारत की रैंकिंग 1 पायदान कम हुई है। लेकिन अभी भी वह शीर्ष देशों में है।

मानव विकास सूचकांक

129 रैंक

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी ताजा मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में एक स्थान ऊपर चढ़कर 129वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण एशिया में भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.640 से बढ़कर 0.647 हो गया है।

ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग

04 रैंक

ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पॉवर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर है।

क्लाइमेट चेंज इंडेक्स के टॉप 10 परफॉर्मर में

00 रैंक

ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर है। साल 2014 में भारत 31वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में चीन और अमेरिका भारत से पीछे हैं।

पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा के साथ 517 पासपोर्ट सेवा केंद्र मौजूद हैं।

- वर्ष 2019 में ही करीब 1 करोड़ लोगों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं। दुनिया के 16 देशों में जाने के लिए भारत के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। इन देशों में जाने के लिए भारतीय पासपोर्ट ही काफी है। ईरान, इंडोनेशिया और म्यांमार सहित दुनिया के कुल 43 देशों ने भारतीय पासपोर्ट धारकों

केंद्र सरकार का लक्ष्य-किसी को भी पासपोर्ट बनवाने के लिए 50 किमी से ज्यादा दूर न जाना पड़े। 5 साल में 5 गुना से ज्यादा पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए। ऑनलाइन के साथ एप से भी आवेदन...

को वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा दे रखी है। इस सुविधा के तहत भारत के नागरिकों को उस देश पहुंचकर एयरपोर्ट इमिग्रेशन से वीजा प्राप्त करना होता है।

- इसी प्रकार श्रीलंका, न्यूजीलैंड और मलेशिया समेत 36 देशों ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए ई-वीजा की सुविधा दे रखी है। इसमें ऑनलाइन ही ई-वीजा मिल जाता है।
- ई-गवर्नेंस योजना के तहत नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा की दिशा में पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ पीपीपी मोड पर भागीदारी की गई है। डाक विभाग के साथ सभी प्रधान डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्रों शुरु किए जाने हैं। अभी तक 424 की शुरुआत भी हो चुकी है। विदेश मंत्रालय का लक्ष्य है किसी को भी पासपोर्ट बनवाने के लिए 50 किमी से ज्यादा की यात्रा न करनी पड़े।
- पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेने के साथ दस्तावेज भी ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं। पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) के साथ ही वर्ष 2018 में 'एम-पासपोर्ट' एप भी शुरु किया गया है।
- एप पासपोर्ट के लिए आवेदन, भुगतान और मिलने का समय तय करने की सुविधा देगा। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में विवाह प्रमाणपत्र समेत कई गैर-जरूरी दस्तावेजों की जरूरत खत्म कर दी गई है। आवेदक देश में कहीं भी रहते हुए पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकता है।
- नई योजना के तहत आवेदक फार्म जमा करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में किसी का भी चयन कर सकता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर आवेदन फॉर्म में दिए गए पते पर पुलिस सत्यापन होगा। इसी पते पर आवेदन के समय चुना गया क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट भेज देगा।
- नए नियमों के तहत आधार कार्ड को भी पते और उम्र प्रमाण पत्र के लिए स्वीकार कर लिया गया है। विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। पासपोर्ट में किसी भी सुधार की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। विदेश मंत्रालय सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर रहा है।
- भारत में जल्द ही आम नागरिकों को ई-पासपोर्ट देने की शुरुआत भी होगी। फिलहाल पासपोर्ट प्रिंटेड रूप में बुकलेट के तौर पर मिलता है। विदेश मंत्रालय ने अभी 20000 अधिकारियों और राजनयिकों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई-पासपोर्ट जारी किए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर चिप लगी हुई है। ई-पासपोर्ट योजना से पासपोर्ट जारी होने की प्रक्रिया आसान होने के साथ और तेज हो जाएगी। साथ ही, किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।
- प्रवासी भारतीय यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को लिए जीवन पर्यंत वीजा सुविधा भी दी गई है।

आधारभूत ढांचा विकास की नई इबारत

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सुविधाओं के साथ पुराने व छोटे शहर व गांव कदमताल करने लगे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़क नेटवर्क देश को कनेक्टिविटी दे रहा है तो पिछले 6 साल में देश के 27 शहरों में दोगुना ऑपरेशनल हुए मेट्रो रेल नेटवर्क ने जनजीवन को नई रफ्तार दी है। वहीं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का एलान किया गया है।

विकास को नई रफ्तार...

- 2014 के मुकाबले 6 साल बाद मेट्रो रेल का नेटवर्क 225 किमी से बढ़कर करीब 450 किमी ऑपरेशन हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण दोगुना गति से हुआ।
- सुदूर क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर हर जगह सड़कों का बिछ रहा जाल। शहरों का विकास अमृत योजना के तहत। सबसे लंबी सुरंग अटल टनल की शुरुआत हुई।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल से सितंबर 2020 के शुरुआती 6 महीने में दैनिक 21.60 किमी की औसत से 3951 किमी सड़क निर्माण किया।
- शहरी सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में 2013-14 में दैनिक 12 किमी निर्माण हो रहा था जो 2016-17 में 19 किमी हुआ। ग्रामीण सड़कें 2011-14 के बीच दैनिक 73.5 किमी बन रही थी जो 2014-17 के बीच 113 किमी दैनिक बनाई है।

> “नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च की तैयारी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए।
> -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नई उम्मीदें

- नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर सरकार ने 110 लाख करोड़ रुपए खर्च का एलान किया है। जम्मू-कश्मीर में जोजिला टनल निर्माण शुरू होने से द्रास और कारगिल के रास्ते श्रीनगर तथा लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर हर मौसम में संपर्क बनेगा।
- दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे पर ई-हाईवे बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, जहां ई-बसें और ट्रक चलेंगे। वित्तवर्ष 2020-21 में 11000 किमी लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य, ठेके भी तीन साल में सबसे अधिक 1330 किमी निर्माण के दिए। 27 शहरों में करीब 1000 किमी मेट्रो नेटवर्क का काम अलग-अलग चरण में जारी।
- सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत 8 लाख करोड़ रुपए के 415 प्रोजेक्ट की पहचान जिससे तटीय क्षेत्रों में रोजगार मुहैया होंगे। 108 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए।

कानूनी जाल से मिली मुक्ति

देश में कार्य संस्कृति बदल रही है। 'टोपी ट्रांसफर' यानी अधिकारी के जिम्मेदारी से भागने की संस्कृति खत्म करके चुनौती स्वीकारने, मजबूत निगरानी और पारर्शिता से काम करने पर जोर है। काम में अवरोधक व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले पुराने और जटिल कानून खत्म करके नए कानून आसान बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "हम न्यू इंडिया के निर्माण के लिए देश में एक पारदर्शी इकोसिस्टम बना रहे हैं जो सरकारी तंत्र पर कम से कम आश्रित हो। पुराने और अप्रसांगिक कानून जहां खत्म करने की जरूरत है, उसे खत्म कर रहे हैं। तो वहीं घर तक न्याय की पहुंच के लिए वर्चुअल कोर्ट, ई-चालान सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तेजी से काम कर रही है।

नया सवेरा

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने दो कार्यकाल में 1800 से अधिक पुराने कानून खत्म कर चुकी है। नए कानूनों को जनकेंद्रित बनाया जा रहा है।
- कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी बनाया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। नागरिकता संशोधन कानून बड़े विरोध-प्रदर्शन को थामते हुए 10 जनवरी, 2020 से लागू।
- केंद्र सरकार ने जुलाई, 2015 में देशभर की सभी अदालतों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण वाली दूसरे चरण की परियोजना को मंजूरी दी थी। इसमें 1670 करोड़ रुपए की लागत से 16845 अदालतों का कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य था।
- सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के शुरुआती महीनों में 7 हजार से अधिक सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से की जिसमें 5 हजार से अधिक वकील सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए।
- जून 2020 से अक्टूबर 2020 तक 15 राज्यों में 27 ई-लोक अदालतें लगी जिसमें 4.83 लाख मामलों की सुनवाई हुई और 1409 करोड़ रुपये के 2.51 लाख मामले निपटाए गए।
- नवंबर, 2020 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में आयोजित ई-लोक अदालतों में 16,651 मामलों की सुनवाई हुई जिसमें 107.4 करोड़ रुपये के 12,686 विवादों का निपटारा हुआ।
- टेली लॉ से चालू वित्त वर्ष के शुरुआती सात महीने में 2.05 लाख लोगों को पंचायत स्तर के कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़कर जरूरमंद को कानूनी सलाह दी गई।

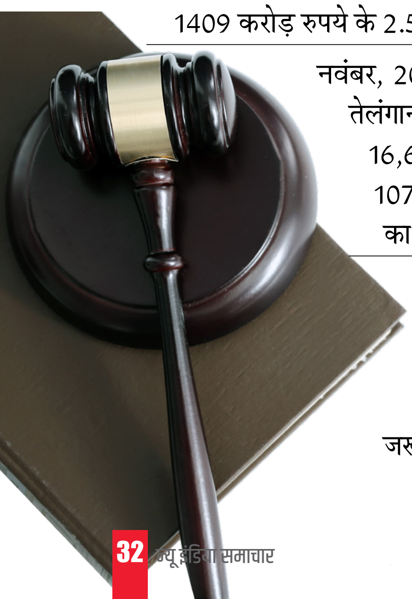

नई उम्मीदें

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पुराने कानूनों के साथ नई सदी का निर्माण संभव नहीं, विकास के लिए सुधार जरूरी है। जहां कानून बदलने की जरूरत है, वहां बदला जा रहा है और जहां कानून खत्म करने की जरूरत है, वहां कानून खत्म किए जा रहे हैं।
- वर्चुअल कोर्ट में मुकदमा लड़ने व ई-केस फाइलिंग के लिए वकीलों को प्रशिक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने देश के वकीलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमे की बहस करने का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।
- केंद्र सरकार में कानून खत्म करने से नागरिकों का जीवन आसान होने को मॉडल मानकर मुख्यमंत्री योगी यादित्यनाथ ने भी यूपी के 100 वर्ष पुराने या बेकार के कानून खत्म कराने का प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा औद्योगिक विकास विभाग को सौंपा है।
- सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड ने पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट में ई-कोर्ट का वर्चुअल उदघाटन कार्यक्रम में कहा-कमेटी ने यह सुनिश्चित करने का दायित्व लिया है कि देश की हर अदालत में ई-सेवा केंद्र बनाए जाएं।
- ई-अदालत परियोजना में देशभर के 2927 अदालत परिसरों को तीव्र गति वाली वाइड एरिया नेटवर्क(डब्ल्यूएएन) से जोड़ा गया, बाकी पर काम तेज गति से जारी।
- सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी की अगुवाई में देशभर में आभासी न्यायालय(जहां सबकुछ ऑनलाइन होता है) की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी तक दिल्ली व महाराष्ट्र में दो, हरियाणा, मद्रास, कर्नाटक, केरल और असम में एक-एक अभासी कोर्ट है। अभी तक इनमें 30 लाख से अधिक मामले निपटाए गए।

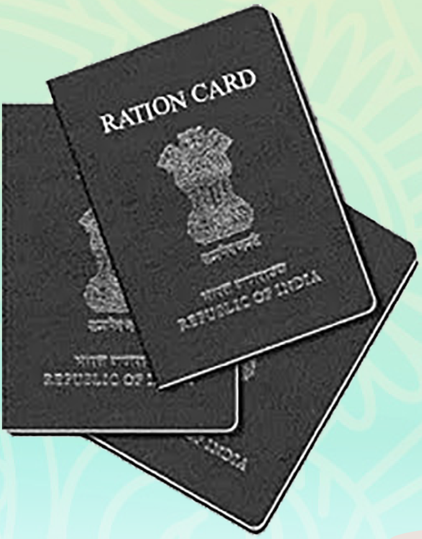

1 देश राशन कार्ड परीक्षा चुनाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने प्रशासनिक सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्टांप पेपर पर शपथपत्र और सत्यापित कागजात जमा कराने की परेशानी सत्ता संभालते ही नवंबर 2014 में खत्म कर दी। एक देश-एक राशन कार्ड 24 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ तो नए साल 2021 में मंत्रिमंडल से मंजूर एक देश-एक परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बार-बार होने वाले चुनाव से थमते विकास और पैसे की बर्बादी रोकने के लिए 'एक देश, एक चुनाव' को सिर्फ चर्चा का मुद्दा नहीं बल्कि देश की जरूरत बताया है।

जो सपने हुए पूरे

- नवंबर, 2014 में केंद्र सरकार ने सरकारी सिस्टम में जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजातों की फोटो कॉपी को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करने की अनिवार्यता खत्म करके स्वयः प्रमाणन की सुविधा दी।
- सरकार के कई कामकाज के लिए जो शपथपत्र बनवाकर देने की अनिवार्यता लागू थी, उसे खत्म करके सादे कागज पर स्वयं घोषणा को स्वीकृति दी गई, इससे समय व स्टांप पेपर सहित अन्य खर्च की बचत हुई
- सरकारी नौकरी के ग्रुप-बी(गैर राजपत्रित), ग्रुप-सी और ग्रुप-डी व समकक्ष पदों पर भर्ती में इंटरव्यू 1 जनवरी, 2016 से खत्म करके सरकार में सिफारिश से नौकरी के रास्ते बंद किए।
- वन नेशन-वन राशन कार्ड देश के 28 राज्यों में लागू, करीब 65 करोड़ लाभार्थी। इसमें कार्ड धारक को देश में किसी भी दुकान पर राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिली। आधार-बायोमैट्रिक से लिंक इस सिस्टम में राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह जुड़ जाएगी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर की ग्रुप-बी और ग्रुप-सी(गैर तकनीकी पद) के लिए केंद्रीय पात्रता परीक्षा कराने वाली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी(एनआरए) बनाने को मंजूरी दी।

नई उम्मीदें और सपने

- नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी(एनआरए) को 1517.57 करोड़ रुपए देशभर में कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट(सीईटी) केंद्र बनाने और परीक्षा कराने के लिए तीन साल में खर्च को मंजूरी दी है।
- रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सलेक्शन बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन के लिए पहले चरण में एनआरए एक साथ 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर की कॉमन परीक्षा साल में दो बार कराएगा।
- नए साल में शुरू होने वाली परीक्षा में शामिल कितनी बार हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होगी लेकिन एक आयु सीमा निर्धारित रहेगी, मिलने वाले अंक की मेरिट बनेगी, जिसकी वैधता 3 साल रहेगी।
- एक देश-एक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनेगा, करीब 20 तरह के भर्ती बोर्ड में परीक्षा देने के लिए बार-बार फार्म भरने में होने वाला खर्च व समय बचेगा।
- एक देश-एक राशन कार्ड प्रोजेक्ट को बाकी बचे हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च, 2021 तक लागू करने को लेकर केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन में एक देश-एक चुनाव को देश की जरूरत बताई है।

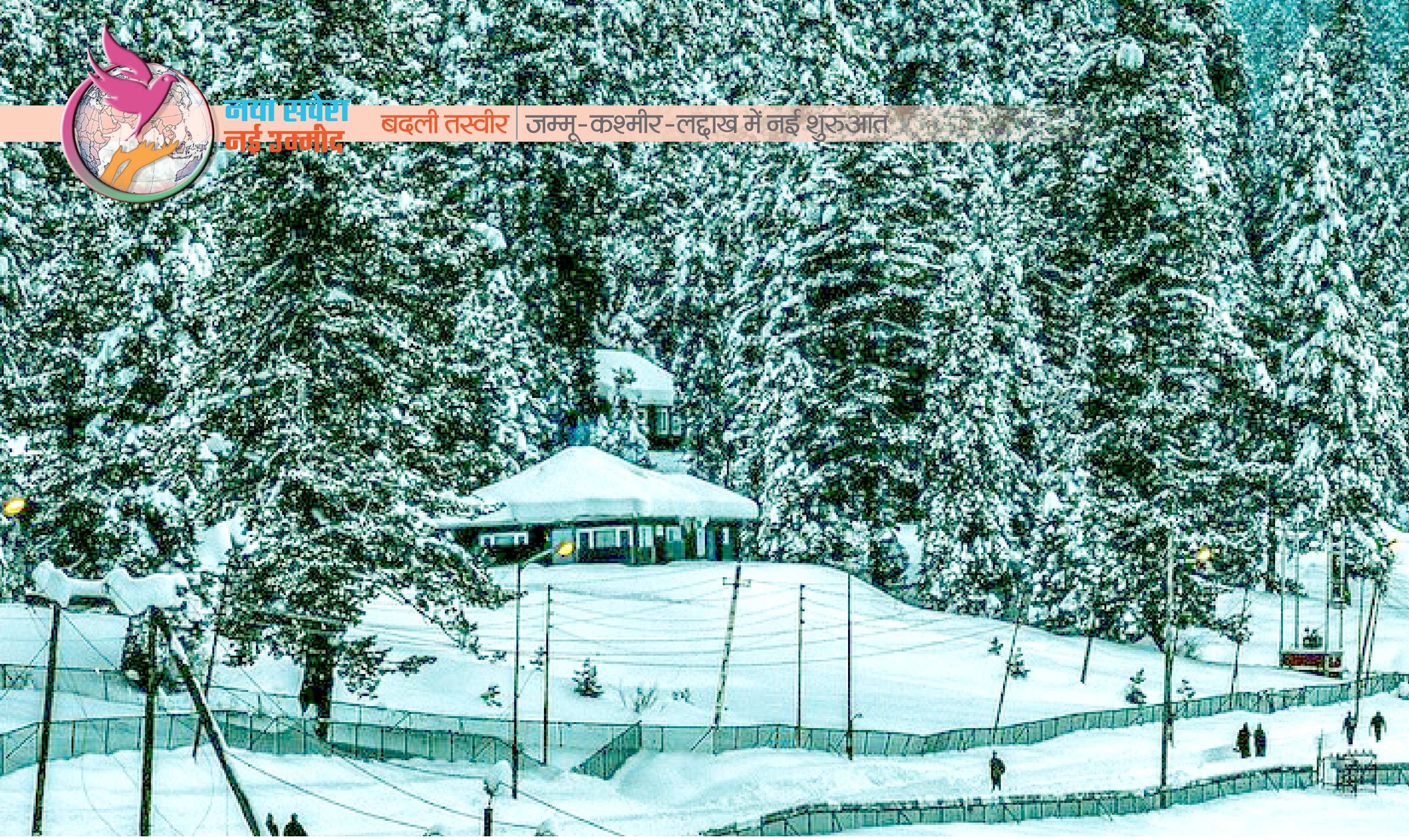

एक देश, एक विधान, एक निशान का सपना साकार

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 'एक देश, एक विधान, एक प्रधान' का संकल्प आजादी के 70 साल बाद पूरा हो पाया है तो अनुच्छेद 370 व 35ए से आजादी के 1 साल बाद धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब देश के बाकी हिस्से के साथ विकास की कदमताल कर रहा है। पुलवामा का उक्खू गांव अब पेंसिल विलेज का दर्जा पाने जा रहा है। देश के बाकी राज्यों के निवासी अब यहां संपत्ति खरीद सकते हैं। जम्मू-कश्मीर की महिलाएं अब कहीं और शादी करने पर पैतृक संपत्ति में अपना अधिकारी नहीं खोएंगी। रोजगार के नए साधनों के साथ अब यहां के युवाओं और स्थानीय निवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बाल विवाह रोकथाम कानून, अमृत योजना, शिक्षा का अधिकार, पीएमजय-आयुष्मान भारत जैसी तमाम लाभकारी योजनाओं का लाभ अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को मिल पा रहा है।

उम्मीदों का सवेरा

अनुच्छेद 370 और 35-ए हटने से बदली कश्मीर की फिजा

- 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने को मंजूरी दी गई। 31 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।
- इसके साथ ही केंद्र सरकार के 170 से ज्यादा कानून यहां लागू हो गए। यहां के स्थानीय निवासियों और दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच अधिकार अब समान हैं। राज्य के 354 कानूनों में से 164 कानूनों को निरस्त किया गया, 138 कानूनों को संशोधित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- 370 से आजादी के एक साल बाद यहां गांवों के साथ जनपद और जिला पंचायत के चुनावों हो रहे हैं।

वंचितों को लाभ

इन योजनाओं में लोगों को मिला लाभ

सौभाग्य योजना	उज्ज्वला योजना	उजाला योजना
3,87,501	12,60,685	15,90,873

सामाजिक सुरक्षा (राज्य) योजना | 5,92,333

1353 बच्चों और 381 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका मिशन इंद्रधनुष के तहत

- आयुष्मान भारत योजना के तहत 11.41 लाख लोगों के हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। 3,48,370 परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है।
- पीएम किसान योजना का लाभ लेने में जम्मू-कश्मीर सबसे आगे है। यहां एक वर्ष में 9.86 लाख लाभार्थी इसमें शामिल हुए हैं। पीएम आवास योजना(ग्रामीण) के तहत 77252 घर स्वीकृत।
- वाल्मीकी समुदाय के लाखों लोग अब जम्मू-कश्मीर के नागरिक बन गए हैं।
- मूल निवासी कानून लागू किया गया। नई मूल निवासी परिभाषा के अनुसार 15 वर्ष या अधिक समय तक जम्मू-कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति अधिवासी माने जाएंगे।
- पश्चिमी पाकिस्तान से उजाड़े और खदेड़े गए शरणार्थियों को भी उनके मानव अधिकार और नागरिक अधिकार मिल गए हैं।
- 1990 में कश्मीर घाटी से भगाए गए कश्मीरी पंडितों के फिर से बसाने का रास्ता साफ हो गया है।
- जम्मू-कश्मीर से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है।

अलग पड़े अलगाववादी/आतंक पर शिकंजा

- अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। 2018 में 58, 2019 में 70 और 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्चे पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2018 में 257, वर्ष 2019 में 157 और सितंबर 2020 तक 180 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। हिंसा की घटनाओं में 35 फीसदी की कमी आई है। पत्थरबाजी की घटनाएं अब न के बराबर ही हो रही हैं।

विकास का विस्तार

- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर रोडमैप तैयार करने के लिए एक मंत्री समूह (GoM) का गठन किया गया है।
- वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जम्मू को 30,757 करोड़ और कश्मीर को 5,959 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- 40 वर्ष से रूकी हुई शाहपुर-कंडी बांध परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है। रातले पनबिजली परियोजना के वर्षों तक लटके रहने के बाद कार्य शुरू किया गया है।
- जम्मू-कश्मीर में दो एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। इनमें से एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में।
- केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 7 मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। 50 नए डिग्री कॉलेज शुरु किए गए हैं। 25000 नई कॉलेज सीटें जोड़ी गई हैं।
- 25 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 85 विकास योजनाओं की शुरुआत की।
- 80,068 करोड़ रुपये वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत विकास परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- केंद्र सरकार ने लद्दाख में बौद्ध अध्ययन केंद्र के साथ पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की योजना को हरी झंडी दी।
- प्रशासनिक सुधारों के तहत उद्योग, पर्यटन, वित्त और पुलिस विभाग की स्थापना की गई है। जम्मू-कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना कर 2273 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- सेब के लिए मार्केट इंटरवेशन स्कीम लागू की गई है। डीबीटी द्वारा भुगतान और केंद्रीय एजेंसी द्वारा परिवहन से सेब की कीमतें स्थिर होंगी।
- भारत में तैयार होने वाली 90 फीसदी पेंसिल का लकड़ी का खोखा पुलवामा के उक्खू गांव में तैयार किया जाता है। इसे केंद्र सरकार अब पेंसिल विलेज का टैग देने जा रही है।
- केंद्र सरकार के प्रयास की बदौलत कश्मीर के केसर को जीआइ टैग के साथ अब दुनिया भर में पहचान मिल रही है।

फिर चमकेगा पर्यटन

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में उन जगहों की पहचान की जा रही है, जो टॉप के टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकते हैं। हिमालय की 137 पर्वत चोटियां विदेशी पर्यटकों के लिए खोली गई हैं, जिनमें 15 चोटियां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हैं। जम्मू और श्रीनगर के लिए मेट्रो की डीपीआर तैयार हो चुकी है।

पूर्वोत्तर की पहचान बनेगा कश्मीर का केसर

भारत में केसर की महक अब सिर्फ जम्मू-कश्मीर के चुनिंदा जिलों तक ही सीमित नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर में भी केसर महकेगा। 'नेशनल मिशन ऑन केसर' के तहत केसर की खेती को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए उपाय किए लेकिन जम्मू-कश्मीर के विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। लेकिन अब पूर्वोत्तर के सिक्किम में केसर उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने वाले पायलट प्रोजेक्ट में केसर के फूलों ने एजेंसियों को नई उम्मीद दी है। क्योंकि कश्मीर के पंपोर और सिक्किम के यांगयांग में जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की समानता से यांगयांग में केसर की नमूना खेती की सफलता को बढ़ावा मिला है, यहां केसर के पौधे फल-फूल रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था, जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा और खुमानी, इनका प्रसार दुनिभर में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इससे पूर्व जम्मू-कश्मीर की धरती पर ही देश में केसर क्रांति का आह्वान किया था और स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में केसर उत्पादन व निर्माण एजेंसी गठित की गई। प्रधानमंत्री मोदी की सोच व आह्वान पर केसर का उत्पादन बढ़ाने में मिशन मोड पर जुटी सरकारी एजेंसियों का लक्ष्य है कि जो अभी तक देश में करीब 17 टन केसर का उत्पादन होता है, उसे कुछ वर्षों में 34 टन तक पहुंचाया जाए। केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के चार-पांच जिलों के विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित है। यहां के पंपोर क्षेत्र को केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है।

- पंपोर क्षेत्र का केसर उत्पादन में मुख्य योगदान है। इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों का स्थान है।
- केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों से जुड़ा है, औषधीय गुणों को कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है।
- केसर के बीजों से निकले पौधे कश्मीर से सिक्किम में ले जाकर रोपे गए थे, वहां ये पौधे फल-फूल रहे हैं।
- भारत सरकार के विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लिकेशन एंड रीच (एनईसीटीएआर) ने पायलट परियोजना में मदद की है।
- सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सिक्किम के यांगयांग की मिट्टी व वास्तविक स्थितियों के परीक्षण में यहां की स्थिति को कश्मीर के केसर उगाने के स्थानों के समान पाया है।
- मानकों के विस्तृत विश्लेषण के परिणाम परिणामों का सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में भी उपयोग करने की योजना है।
- भारत में 17 टन केसर उत्पादन होता है। जम्मू-कश्मीर इकलौता राज्य है। कश्मीरी केसर की कीमत 1.60 लाख से करीब 3 लाख रुपए प्रति किलो है। विश्वभर में पैदा होने वाली करीब 300 टन केसर में 90% ईरान में होता है।

सीमा सुरक्षा बल
सरहदें सुरक्षित हैं इनके दम से

एक सीमा रक्षक की प्रतिज्ञा

मैं कभी भी एक सीमा रक्षक के शस्त्रों का अपमान नहीं करूंगा, न ही अपने साथी को कभी अकेला छोड़ूंगा जो मेरे साथ खड़ा होता है। चाहे अकेला हूं या कईयों के साथ हूं, मैं उस हरेक चीज की रक्षा करूंगा जो मेरे देश के लिए पवित्र है।

130 करोड़ देशवासी अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ) के जवान जान की बाजी लगाकर मुस्तैदी के साथ भारत मां की सेवा में तैनात हैं। 55 सालों से हमारी सीमाओं की हिफाजत कर रही बीएसएफ एकमात्र सुरक्षा बल है जिसकी भूमिकाएं युद्ध काल और साथ ही साथ शांति काल में खास तौर पर परिभाषित हैं। भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है। भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन किया गया था। बीएसएफ को युद्ध काल, शांति या नो-वॉर-नो-पीस (एनडब्ल्यूएनपी) के मौकों पर जो भी काम सौंपे गए हैं, उनमें प्रत्येक में उसने अपनी काबिलियत सफलतापूर्वक साबित की है। हमारी सीमाओं की अखंडता की रक्षा करने के अलावा, बीएसएफ को शांति काल में सीमावर्ती क्षेत्रों की पुलिसिंग सुनिश्चित करने और सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोकने का जिम्मा भी सौंपा

आधुनिकीकरण की राह पर बीएसएफ

भारत की पूर्वी सीमा पर मिजोरम में तैनात बीएसएफ के जवानों ने 28 सितंबर 2020 को राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा हथियारों की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया और 29 एके सीरीज राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद जब्त किया। सभी बाधाओं के बावजूद बीएसएफ ने इन सब कोशिशों को पूरी सफलता से नाकामयाब कर दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए बीएसएफ आधुनिकीकरण की राह पर चल पड़ा है और ऑपरेशनों के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से नई तकनीक को अपना रहा है जिसमें नवीनतम हथियारों, संचार व निगरानी प्रणालियों, आधुनिक गैजेट्स और प्रौद्योगिकियों की खरीद शामिल है ताकि वो समय के साथ चल सके और सीमा का बेहतर प्रबंधन और प्रभुत्व बरकरार रख सके। आधुनिकीकरण के चरणों में कई घातक हथियार और तकनीक भी शामिल हैं -

1. **प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सॉल्यूशंस**
2. **निगरानी उपाय**
3. **नाइट फाइटिंग डॉमिनेंस**
4. **बेहतर फायर पावर**
5. **गैर-घातक दंगा नियंत्रण उपकरण**
6. **पुख्ता संचार**
7. **युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली, और**
8. **प्रशिक्षण सहायता उपकरण**

इसके अलावा व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के हिस्से के तौर पर अतिसंवेदनशील इलाकों के लिए तकनीकी समाधानों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें उचित कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ कई सेंसर्स और निगरानी उपकरणों का एकीकरण शामिल है।

कोविड काल में बीएसएफ बना सहारा

- कोविड-19 महामारी के वर्तमान माहौल में सीमा प्रहरियों के समर्पित प्रयास तारीफ के काबिल रहे हैं।
- देश के विभिन्न इलाकों में तैनात बीएसएफ के सदस्यों ने जिस ढंग से लोगों को जागरूक किया है, और साथ ही मुफ्त राशन वितरण, चिकित्सा शिविर और प्लाज्मा दान करने के मुश्किल काम में जिस तरह लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है वो बहुत ही सराहनीय है।
- केंद्र सरकार के राष्ट्रीय उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सीमा सुरक्षा बल जमीनी स्तर पर विशेष अभियान चला रहा है।
- सीमा की सुरक्षा करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी के अलावा ये बल सीमावर्ती कस्बों और गांवों के युवाओं को केंद्रीय बलों में उनकी भर्ती के बारे में जागरूक करके आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।
- नागरिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ बीएसएफ अपने सामाजिक दायित्वों का भी उत्कृष्ट रूप से निर्वहन कर रहा है।

जाता है।

बीएसएफ में 192 बटालियन हैं, जिनमें 3 आपदा प्रबंधन बटालियन शामिल हैं। इनकी कुल क्षमता 2.65 लाख से ज्यादा बहादुर पुरुषों और महिलाओं की है। आर्टिलरी रेजिमेंट, एयर एंड वाटर विंग, ऊंट दस्ते, डॉग स्क्वॉड, कमांडो यूनिट, कम्युनिकेशन सेट-अप, मजबूत प्रशिक्षण ढांचे और अच्छी तरह सुसज्जित चिकित्सा ढांचा भी इसका अंग है। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जिसे ₹भारत की पहली सुरक्षा पंक्ति₹ कहा जाता है।

सीमा सुरक्षा बल 'जीवन पर्यंत कर्तव्य' के मूलमंत्र पर चलता

देश सेवा में सदैव तत्पर

- वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसमें सीमा पार आतंकवाद, युद्ध विराम का उल्लंघन, राष्ट्र-विरोधी तत्वों को मदद करने के लिए ड्रोन विमानों के जरिए हथियार गिराना, नारकोटिक्स की तस्करी और सुरंगों के जरिए घुसपैठ की कोशिशें शामिल हैं।
- 20 जून 2020 को बीएसएफ के सतर्क जवानों ने जम्मू के कठुआ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया।
- 22 अगस्त 2020 को बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के खेमकरण इलाके में सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया और पांच आतंकवादियों को मार गिराया और भारी मात्रा में हथियार-गोला बारूद और नशीले पदार्थों को जब्त किया।
- 09 सितंबर 2020 को राजस्थान के गंगानगर इलाके में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और दो पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया।
- 08 नवंबर 2020 को कश्मीर में एलओसी पर ड्यूटी करते हुए कैप्टन सुदीप सरकार ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया और दो आतंकवादियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कैप्टन सुदीप सरकार ने शहादत पाई।
- 22 नवंबर 2020 को जम्मू के सांबा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के सतर्क सैनिकों ने पाकिस्तान की ओर बनी एक सुरंग का पता लगाया, जिसका इस्तेमाल 19 नवंबर 2020 को नगरोटा में मारे गए आतंकवादियों ने किया था।
- ऐसे वक्त में जब बीएसएफ देश के लिए अपनी समर्पित सेवा के 55 वर्षों का जश्न मना रहा है, तब इसकी परिचालन संबंधी उपलब्धियां दरअसल हमारी सीमाओं की अखंडता को बनाए रखने में उसकी क्षमताओं और प्रतिबद्धता का ही प्रतिबिंब हैं।

है। उसके बहुत से महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। अपने निर्माण के बाद के शुरुआती वर्षों में ही उसने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध फैलने से पहले ही मुक्तिवाहिनी को उसकी तैयारियों में सहायता करने का काम बीएसएफ को सौंपा गया था। मई-जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बीएसएफ, सेना के साथ मिलकर अपनी कमान में पूरी ताकत के साथ देश की अखंडता की रक्षा करते हुए पर्वतों की ऊंचाइयों पर बनी रही।

बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर रहा है जिसमें जम्मू और कश्मीर में सबसे दुर्गम बर्फ से ढके पहाड़, राजस्थान में रेगिस्तान, गुजरात में क्रीक क्षेत्र, बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, असम का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और मिजोरम व त्रिपुरा में मलेरिया के खतरे से प्रभावित घने जंगल शामिल हैं। बीएसएफ को भारतीय सेना के साथ नियंत्रण रेखा पर भी तैनात किया जाता है। इसके अलावा 1965 में अपनी स्थापना के बाद से बीएसएफ को बड़े पैमाने पर पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा और काउंटर इंसर्जेंसी संबंधी जिम्मेदारियों के लिए तैनात किया जाता है। मार्च 1990 में बीएसएफ को जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए शामिल किया गया था। 1990 से 2005 तक वहां आतंकवाद के सबसे कठिन चरण के दौरान ये बल वहां आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगा रहा और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को ढेर किया। इसमें बीएसएफ ने सफलतापूर्वक 11000 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और 1000 से ज्यादा आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करवाया। आंतरिक इलाकों की बात करें तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में वामपंथी चरमपंथ को खत्म करने के लिए बीएसएफ के जवान दिसंबर 2009 से वहां तैनात हैं।बीएसएफ ने अपने समर्पण और निर्भीक पेशेवर रवैये के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा, काउंटर इंसर्जेंसी और नक्सल विरोधी ऑपरेशंस में राष्ट्र के सुरक्षा प्रतिष्ठानों के बीच एक ऊंचा मुकाम भी हासिल किया है। इन बीते वर्षों में इस बल के 1922 कर्मियों ने मातृभूमि की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के पवित्र कर्तव्य की राह में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है।

हर साल बीएसएफ संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में सेवा देने के लिए अपने कई सैनिकों को भेजता है। दुनिया का ये सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बदलते समय और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखते हुए आधुनिक संसाधनों से लैस होकर आगे बढ़ रहा है। बीएसएफ ने साहस और कड़ी मेहनत के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा की है, जिसके लिए उसने न केवल प्रशंसा अर्जित की है बल्कि सीमावर्ती इलाकों की आबादी का भरोसा और सहयोग भी जीता है।

गन्ना किसानों के हित में कदम तो डिजिटल सपना भी होगा साकार

भारत के डिजिटल आधार को मजबूती देना हो या फिर कोरोना काल में जिन लोगों के रोजगार प्रभावित हुए उन्हें सहूलियत देना या 5 करोड़ गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रु. देना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहम फैसले लिए हैं:

- **फैसला: गन्ना किसानों को सीधे बैंक खाते में 3500 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी।**
- **प्रभाव:** 5 करोड़ किसान और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
- चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी। नए रोजगार भी बढ़ेंगे।
- अतिरिक्त उत्पादन का ईंधन ग्रेड इथेनॉल के निर्माण में उपयोग।
- **फैसला: डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा (पीएम-वाणी) को मंजूरी दी।**
- **प्रभाव:** पीएम-वाणी योजना का उद्देश्य पूरे भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के प्रसार को बढ़ावा देना है।
- सूचना क्रांति आईटी भूख के इस दौर में पीएम-वाणी से गांव में बच्चे किताब डाउनलोड कर लेंगे, पढ़ सकेंगे, नए कौशल सीख कर व्यवसाय कर सकेंगे। सुदूर क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, छोटे-मझोले कारोबारियों की आय, बेहतर जीवन स्तर और व्यवसाय की सुगमता में बढ़ोतरी होगी।
- **फैसला: देश के द्वीपों को समृद्ध और संचार से लैस करने के संकल्पों के तहत कोच्चि और लक्षद्वीप समूह के बीच 1072 करोड़ रु. की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी।**
- प्रभाव: इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को विस्तार मिलेगा क्योंकि लक्षद्वीप का ब्लू वाटर यहां की खुबसूरती है जहां देश-दुनिया से लोग पहुंचते हैं। इससे रोजगार सृजन के अलावा सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
- केरल के कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के अगले एक हजार दिनों यानी मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- **फैसला: आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू जिसमें 22,810 करोड़ रु. खर्च की अनुमति।**
- **प्रभाव:** कोरोना के समय जिनकी नौकरियां प्रभावित हुई है उन्हें राहत देने के लिए सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक शामिल सभी नए कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सरकार सब्सिडी देगी।
- जिन रोजगार देने वाले संगठनों में 1 हजार कर्मचारी हैं वहां केंद्र सरकार दो साल के लिए कर्मचारी और नियोक्ता का पूरा 24 फीसदी ईपीएफओ अंशदान सरकार देगी। इसमें नए कर्मचारियों के लिए भी ईपीएफ में 12 फीसदी योगदान सरकार देगी।
- जिनका मासिक वेतन 15 हजार से कम है। ये योजना उन सब पर लागू होगी।

इस अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में 4जी सुविधा के लिए 2374 गांवों में 1533 नए टावर लगाने को मंजूरी दी है। वहीं, पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बिजली वितरण की अंतरराज्यीय व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 6700 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी भी दी गई है। उपभोक्ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी को भी मंजूरी मिल गई है।

Narendra Modi @narendramodi

नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं।

पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे और कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रखते हुए होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं।

Rajnath Singh @rajnathsing

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमारा जो Comprehensive और Integrated Approach है, उसके काफी Positive outcomes देखने को मिले है।

हमारे लिए रक्षा और सुरक्षा में 'This is the End' नहीं होता बल्कि 'We will always go on' होता है।

Amit Shah @AmitShah

नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगा जो देशवासियों की आशाओं और आकाँक्षाओं को पूर्ण करने का केंद्र बनेगा।

मोदी सरकार देश के गरीब व वंचित वर्ग को सशक्त करने में पूरी निष्ठा व समर्पण से जुटी है और यह नया संसद भवन हमारे इस संकल्प को चरितार्थ करने का साक्षी बनेगा।

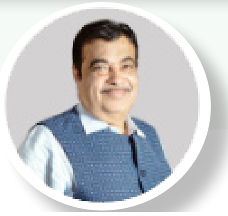

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

ग्रामीण इकोनॉमी को बल मिले और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो इसलिए Khadi and Village Industries Commission के माध्यम से हम जल्द ही गाय के गोबर से बना 'वैदिक पेन्ट' लॉन्च करने वाले हैं। @ChairmanKvic

Ravi Shankar Prasad @rsprasad

पहले सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम को बनाया जा रहा है।
ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी यही हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है: PM

Prakash Javadekar @PrakashJavdekar

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 14 दिसंबर तक कुल 380 LMT धान MSP मूल्यों पर खरीदा, जो कि पिछले वर्ष की इस ही अवधि की तुलना में लगभग 21% अधिक है।

इस वर्ष 42 लाख किसानों को ₹71,778 करोड़ का भुगतान किया गया है।

हर गांव को सड़क से जोड़ने का पीएम मोदी का सपना साकार करने में जुटी सरकार

अब तक 12 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़क का हुआ निर्माण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को तवज्जों, राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता

देहरादून। हर गांव को बेहतर सड़क से जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने में भी त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2017-18 में प्रदेश सरकार अपनी इस कोशिश के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी हासिल कर चुकी है।

प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सड़कों की अर्थव्यवस्था के विकास में खास भूमिका है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क संयोजकता को सरकार ने अपने स्तर पर खास तवज्जो दी है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1872 बस्तियों को सड़कों को जोड़े जाने का लक्ष्य है। इसकी तुलना में दिसंबर 2019 तक 1425 बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रदेश में 25 दिसंबर 2000 से शुरू की गई थी। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 और पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना तय किया गया था। वर्तमान में 42 योजना क्रियान्वयन इकाइयों की मदद से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है।

प्रदेश सरकार ने यह महसूस किया कि ग्रामीण उत्तराखंड की तस्वीर को बदलने के लिए सड़क संयोजकता या कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। बेहतर सड़कों का जाल ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला साबित होगा। इसी को देखते हुए ग्रामीण सड़कों के निर्माण को त्रिवेंद्र सरकार ने प्रमुखता दी। इसी कोशिश का परिणाम रहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण में उत्तराखंड राज्य को 2017-18 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2017-18 में 1500 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 1839 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। यह पुरस्कार भी राज्य को पर्वतीय श्रेणी के राज्यों में मिला था। 207 बसावटों को सड़कों से जोड़ने पर देश के राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को दसरा स्थान हासिल हुआ था।

1872 बस्तियों को सड़कों को जोड़े जाने का लक्ष्य

मैदानी क्षेत्रों में 500 और पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी को सड़कों से जोड़ा जाना था।

42 योजना क्रियान्वयन इकाइयों की मदद से वर्तमान में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है।

सड़क संयोजकता को बढ़ाने में लगाई ताकत

देहरादून। प्रदेश में रेल और वायुमार्ग के साधन सीमित होने के कारण सड़कें हीं यातायात और माल ढुलान का मुख्य साधन हैं। इसी वजह से सड़क और पुल को प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है।

राज्य में वर्ष 2016-17 में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई 322.93 किलोमीटर थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसे 2030 तक बढ़ाकर 461.29 किया जाना तय किया है। यह सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम रहा कि 31 मार्च 2018 तक ही प्रदेश में प्रति लाख की जनसंख्या पर सड़क की लंबाई 428.58 किलोमीटर तक पहुंचा दी गई। 31 मार्च 2018 तक ही प्रदेश में समस्त सड़कों की कुल लंबाई 46 हजार किलोमीटर हो गई।

46 हजार किमी सड़क का प्रदेश में है नेटवर्क

508 करोड़ से बनेंगी सड़कें और पुल, दो साल में काम होगा पूरा

केंद्रीय सड़क निधि के तहत उत्तराखंड में 33 मार्ग और पुल स्वीकृत हुए हैं। इन पर 508.77 करोड़ पर खर्च होंगे। ये कार्य अगले दो साल में पूरे होने हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 30 कार्यों के लिए 316 करोड़ की मंजूरी दी। वर्तमान में 19 कार्यों पर काम चल रहा है। सात कार्यों में निविदा की कार्यवाही गतिमान है। दो कार्यों के अनुबंध गठित किए जा रहे हैं।

मसूरी में बनेगी टनल जाम से मिलेगी निजात

पहाड़ों की रानी मसूरी में ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एक डबल लेन टनल का निर्माण होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी ...

त्यूनी- टिहरी-मलैथा मार्ग होगा डबल लेन

मंत्रालय ने त्यूनी टिहरी और मलेथा नेशनल हाईवे को भी डबल लेन करने पर सहमति दे दी है। करीब मार्ग की कुल लंबाई 311 किमी है। इस मार्ग के चौडीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण को ...

मोदी ने 'स्वर्णिम विजय मशाल' प्रज्ज्वलित की

पंजाब केसरी/नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से "स्वर्णिम विजय मशालें" प्रज्ज्वलित कर उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में रवाना किया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे। इस मौके पर रक्षा राज्यमंत्री ...

मशाल 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांवों सहित देश के विभिन्न भागों में पहुंचेगी

नेशनल वार मैमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्ज्वलित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

अन्य वरिष्ठ सिविल व सैन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ... आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी व्यक्त किए।मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक ... जलती रहने वाली ज्योति से मशालें ... उन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांवों सहित देश के विभिन्न भागों के लिए ...

पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन कर लाभ उठाएं स्ट्रीट वेंडर्स

नई दिल्ली (एसएनबी)। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के तहत स्ट्रीट वेंडर्स निगम द्वारा वार्डों में आयोजित कैंपों के जरिए आवेदन कर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ीठेलाप्पटरी लगाने वाले 10 हजार रुपए तक का सिक्योरिटी फ्री ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही नियमित भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी, समय से भुगतान पर अगली बार इस से बड़ा ऋण व डिजिटल लेनन्देन पर साल में 1200 रुपए तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में आयोजित कैंप में 31 दिसम्बर तक सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ...

एएमयू के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी

एनबीटी न्यूज, अलीगढ़: एएमयू के सौ साल पूरे होने पर 22 दिसंबर को शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि विडियो लिंक से शामिल होंगे। उनके साथ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी होंगे। कुलपति प्रो. तारीक मंसूर ने ... की स्वीकृति मिलने की जानकारी साझा करते हुए कहा कि एएमयू की बेहतरी की राह खुलेगी। प्रो. मंसूर ने कहा कि कार्यक्रमों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ...

भारत-बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद रेल सेवा शुरू

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भारत-बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच रेल लाइन 1965 से बंद है। हालांकि, अभी मालगाड़ियां ही चलेंगी।

मोदी ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शेख हसीना से कहा, कोरोना के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग रहा है। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को गति देते हुए हाइड्रोकार्बन, कृषि और कपड़ा जैसे विविध क्षेत्रों में सात ...

शिखर सम्मेलन

- पीएम ने चिल्हाटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया
- आपसी सहयोग को गति देते हुए दोनों देशों ने सात समझौते किए

संपर्क बढ़ने की उम्मीदः चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल संपर्क से असम-बंगाल से बांग्लादेश के लिए संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच 1965 तक मुख्य ब्राडगेज संपर्क का एक हिस्सा था। मोदी और हसीना ने बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

संबंधों में मजबूती पेज 11

सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग

इसरो ने कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया कोरोना काल में दूसरा, साल का आखिरी मिशन

श्रीहरिकोटा | भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से गुरुवार को कम्युनिकेशन सैटेलाइट (सीएमएस-01) की लॉन्चिंग की। यह लॉन्चिंग दोपहर तीन बजकर 41 मिनिट पर पीएसएलवी-सी50 रॉकेट से की गई। कोरोना काल में किसी सैटेलाइट की यह महज दूसरी लॉन्चिंग हैं। सीएमएस-01 भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह भारत के ...

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
1 से 15 जनवरी , 2021

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर - DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या U (S)-98/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि - 18 दिसंबर 2020, कुल पृष्ठ-44)

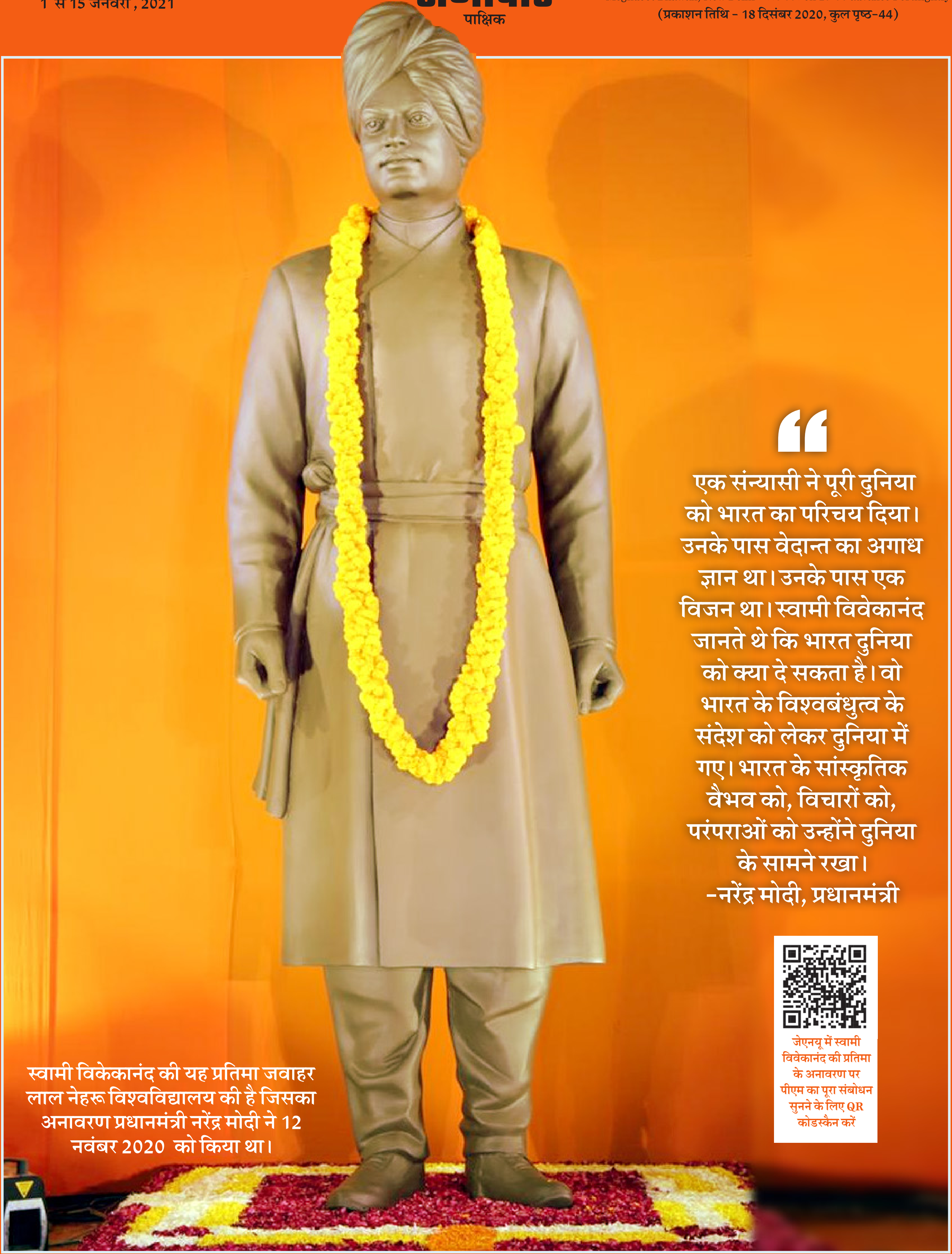

"एक संन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। उनके पास वेदान्त का अगाध ज्ञान था। उनके पास एक विजन था। स्वामी विवेकानंद जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। वो भारत के विश्वबंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण पर पीएम का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोडस्कैन करें

स्वामी विकेकानंद की यह प्रतिमा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2020 को किया था।

संपादक:
कुलदीप सिंह धतवालिया, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश महानिदेशक, बीओसी (ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20